



जिला परिषद जयपुर में हुई भ्रष्टाचार की हदें पार..

सांसद-विधायक कोष में सेंध; करोड़ों की हेराफेरी!

नमस्ते राजस्थान

जयपुर/झाबर सिंह धायल। जिला परिषद जयपुर यानि भ्रष्टाचार का गढ़.. ऐसा हम नहीं कहते बल्कि यहां हर दूसरे दिन सामने आने वाले कारनामों ही इसकी कहानी बर्ना करने के लिए काफी है। लेकिन इस बार जयपुर जिला परिषद में इस भ्रष्टाचार की हदें पार हो गई हैं और इसमें कई बड़े जिम्मेदार अधिकारियों के काले कारनामों भी सामने आ रहे हैं। मामला जुड़ा है सांसद और विधायक कोष से स्वीकृत होने वाली वित्तीय स्वीकृतियों का जिम्मे बड़े स्तर पर घोटाला उजागर हुआ है। दरअसल, सांसद और विधायक कोष से निर्माण कार्यों के नाम पर स्वीकृत राशि से अधिक राशि का मूल्यांकन कर कमीशन के लालच में ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का खेल जिला परिषद में किया गया और तत्कालीन जिला परिषद सीईओ शिल्पा सिंह के संज्ञान में होने के बावजूद प्रकरण को दबाने का प्रयास किया गया और इस कारनामों में लिप्त कार्मिकों पर कोई कार्रवाई करना तक जरूरी नहीं समझा गया। एक आंकलन के अनुसार सांसद एवं विधायक कोष से हुए लगभग 1.25 करोड़ रुपए की राशि के निर्माण कार्यों में इस कमीशन के खेल को अंजाम दिया गया। यहां जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा टेंडर प्रीमियम (टीपी) राशि के नाम पर कमीशन के लालच में ठेकेदार को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। हालांकि जिला परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार, अधिकारियों को भ्रष्ट एवं भ्रष्टाचार के प्रकरणों में लिप्त कार्मिकों पर मेहरबान होने सहित राजकार्य में मनमर्जी करने का यह कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे अनेक मामले जिला परिषद जयपुर की संस्थापन जांच शाखा में धूल फांक रहे हैं जो कार्रवाई के लिए लम्बित हैं। परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार सहित अधिकारियों की मनमर्जी करने की कार्यशैली के अनेक मामले सामने आ रहे हैं लेकिन जिला परिषद के गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई असर नहीं हो रहा है। ताजा मामले की बात करें तो विभिन्न कार्यों के लिए स्वीकृत राशि में से टीपी की राशि काटी जानी थी लेकिन नियम विरुद्ध अधिक राशि का मूल्यांकन कर कुल मूल्यांकन राशि में से नियम विरुद्ध टीपी राशि काट दी गई। विभागीय नियमानुसार यदि स्वीकृत राशि से अधिक राशि का मूल्यांकन होता है तो सीईओ को उच्च अधिकारियों से जांच करवानी चाहिए थी लेकिन सीईओ शिल्पा सिंह ने प्रकरण में जांच नहीं करवाकर महज लौपावती कर दी।

■ सांसद एवं विधायक कोष में स्वीकृत कार्यों में कमीशन के लालच में हुआ खेला

● सहायक अभियंता के इस काले कारनामों को मिला तत्कालीन जिला परिषद सीईओ का संरक्षण

● गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को दबाने का किया प्रयास

■ स्वीकृत राशि से अधिक राशि का मूल्यांकन करते हुए अधिक राशि के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर राजकोष को लगाया लाखों का चूना

■ स्वीकृत राशि से अधिक मूल्यांकन कर फिर उस राशि में से टेंडर प्रीमियम राशि काटकर भुगतान करने की प्रक्रिया कर उक्त कार्य का समायोजन

संभागीय आयुक्त ने शिकायत पर जांच कमेटी बनाई

कार्रवाई शून्य



करोड़ों की हेराफेरी का पूरा गणित समझाना है जरूरी, ऐसे चल रहा है कमीशन का खेल

दरअसल सांसद और विधायक के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्य कराने के नाम पर अपने कोष से राशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें सम्बन्धित विकास कराए जाते हैं। उदाहरण के लिए पूर्ववर्ती सरकार में सांगानेर से विधायक लाहोटी के द्वारा सीसी सड़क निर्माण कार्य वर्क आर्डर संख्या 2022.23 /27091 जिसकी वित्तीय स्वीकृति 6736.39 दिनांक 14.03.2023 स्वीकृत राशि 10 लाख रुपये जिसमें कार्यकारी एजेंसी विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगानेर जयपुर को निर्धारित किया गया। उक्त कार्य की मूल्यांकन राशि 10 लाख 70 हजार



851 रुपये की गई तथा भुगतान के लिए अनुमत राशि 9 लाख 64 हजार 574 को समायोजन योग्य माना। जबकि विभागीय नियमानुसार स्वीकृत राशि में से टेंडर प्रीमियम राशि को काटकर भुगतान किया जाना होता है। लेकिन यहां अधिकारियों ने कमीशन के लालच में ठेकेदार से मिलीभगत कर अनेक निर्माण कार्यों में स्वीकृत राशि से अधिक मूल्यांकन कर फिर उस राशि में से टेंडर प्रीमियम राशि काटकर भुगतान करने की प्रक्रिया कर उक्त कार्य का समायोजन करने का खेल कर दिया। यानी स्वीकृत राशि 10 लाख में से टेंडर प्रीमियम राशि काटने सहित अन्य कटौतियां काटकर भुगतान किया जाता जो नहीं किया गया।

● तत्कालीन जिला परिषद सीईओ सहित कई अन्य कार्मिकों पर गंभीर आरोपों की की गई शिकायतें, कार्रवाई ज़ीरो

शिकायतों के अनुसार सहायक अभियंता हरीश वर्मा के इस भ्रष्टाचार में नितेश टाटीवाल सहित आकाश गुप्ता मुख्य रूप से संलिप्त बताए जा रहे हैं। आकाश गुप्ता, सांख्यिकी अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे और गुप्ता को नियम विरुद्ध और बिना किसी आदेश के एम.पी/एमएलए की स्कीम का चार्ज दिया गया बताया गया। शिकायतों के अनुसार जिला परिषद जयपुर में हरीश वर्मा के सानिध्य में भ्रष्टाचार की एक गैंग के तहत भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन आरोपियों द्वारा बिना वार्षिक कार्य योजना के अनेक कार्यों की अनेक स्वीकृतियां फर्म और ठेकेदार से मिलीभगत कर नियम विरुद्ध जारी की गई। इसके साथ ही शिकायतों में सुमन देवी द्वारा और तत्कालीन शिल्पा सिंह का संरक्षण होने की बात भी सामने आई है।

गंभीर वित्तीय अनियमितताएं आई सामने, जिम्मेदारों ने ही राजकोष को लगाया करोड़ों का चूना

इस प्रकार पंचायत समितियों से लेकर जिला परिषद जयपुर में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम देते हुए राजकोष को चूना लगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिला परिषद जयपुर के सीईओ और एपीईओ ऐसे गंभीर भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के मामलों का संज्ञान में आने के बावजूद भी प्रकरणों में लिप्त कार्मिकों पर कार्रवाई करने की बजाय मेहरबानी हटते हुए संरक्षण देने का काम करते रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह भी सामने आया है कि जिला परिषद की सीईओ शिल्पा सिंह के सामने ऐसे अनेक मामले पहुंचे हैं लेकिन इन मामलों में लिप्त कार्मिकों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि सामने तो यह भी आया है कि सीईओ शिल्पा सिंह ने बेकडेट में ऑफलाइन पत्रावली चलवा कर कई गड़बड़ियों को भी अंजाम दिया है।

■ सहायक अभियंता हरीश वर्मा को मिलता रहा संरक्षण, लगातार चलता रहा कमीशन का खेल

सामने आई शिकायतों के अनुसार सहायक अभियंता हरीश वर्मा द्वारा पंचायत समिति सांगानेर में पूर्व विधायक गंगा देवी द्वारा स्वीकृत कार्यों में मूल्यांकन करने के लिए अधिकृत नहीं होने के उपरांत भी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म से मिलीभगत कर नियम विरुद्ध एवं फर्जी एमबी/यूसी/सीसी भरने का गंभीर अपराध कर फर्जीवाड़े सहित गंभीर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। इस एक प्रकरण में सहायक अभियंता हरीश वर्मा द्वारा अनाधिकृत रूप से 27 लाख के निर्माण कार्यों की फर्जी सीसी बिना भौतिक सत्यापन और गुणवत्ता जांच किये ही नियम विरुद्ध जारी कर दिए गए। दरअसल, हरीश वर्मा पर पिछले कई वर्षों से कई बार पदस्थापित रहने के दौरान गंभीर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग सहित गंभीर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के आरोप लग चुके हैं।

पुतिन ने नई परमाणु नीति पर किए हस्ताक्षर, बाइडन के फैसले से एटमी जंग के मुहाने पर दुनिया?



नमस्ते राजस्थान

मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को एक अहम फैसले के तहत संशोधित परमाणु नीति पर हस्ताक्षर किए हैं। इस नई नीति के तहत अगर कोई देश किसी परमाणु युद्ध संपन्न देश की मदद से रूस पर हमला करता है तो इसे देश पर संयुक्त हमला माना जाएगा और उस स्थिति में रूस की सरकार परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकेगी। हालांकि इस स्थिति में कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। पुतिन का यह फैसला रूस-यूक्रेन युद्ध के एक हजार दिन पूरे होने के अवसर पर सामने आया है।

जो बाइडन के फैसले ने बढ़ाया परमाणु युद्ध का खतरा?

अमेरिका में जो बाइडन की सरकार ने जाते जाते यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के भीतर हमले की मंजूरी दे दी है। इस पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही थी। पुतिन द्वारा संशोधित परमाणु नीति पर हस्ताक्षर के कदम को भी बाइडन के फैसले का ही जवाब माना जा रहा है। रूस की नई परमाणु नीति में ये प्रावधान किया गया है कि रूस पर अगर बड़े पैमाने पर हवाई हमला होता है तो उसके जवाब में रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन की सेना द्वारा अमेरिकी की लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल पहले भी किया जा रहा था, लेकिन ये इस्तेमाल सिर्फ सीमावर्ती इलाकों तक सीमित था। अब सत्ता से जाते जाते बाइडन ने बड़ा फैसला लेते हुए यूक्रेन को रूस के भीतर भी लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले की मंजूरी दे दी है।

महाराष्ट्र चुनाव से एक दिन पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप, 9 लाख नकद जब्त

नमस्ते राजस्थान

मुंबई। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले कैश कांड सामने आया है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप लगाया गया है। इस बीच चुनाव आयोग की शिकायत पर विरार के तुलिन पुलिस स्टेशन में ये केस रजिस्टर्ड हुआ है। बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक पर भी केस दर्ज हुआ है। पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे के मुताबिक कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने करीब 9 लाख से ज्यादा कैश और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किये हैं।

पत्ताङ्ग ने मौके से कैश किया बरामद- मुख्य चुनाव अधिकारी

वहीं इस मामले पर अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी महाराष्ट्र किरण कुलकर्णी ने कहा कि सभी चीज अंडर कंट्रोल में हैं, हम लॉ के अनुसार काम करेंगे। उन्होंने बताया कि नालासापारा में हुआ।



सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। आचार संहिता का पालन करने के लिए गठित चुनाव मशीनरी की पत्ताङ्ग भी मौके पर पहुंची। पत्ताङ्ग ने परिसर का जायजा लिया और कुछ जब्ती भी की है दरअसल, वसई विरार में बहुजन विकास आघाड़ी ने लगाया विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाया था। इस आरोप में पालघर के नालासापारा में बीजेपी और बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ झगड़ा भी हुआ।

बेनीवाल की चेतावनी के बाद हरकत में आई सरकार, सीबीआई करेगी अनीता चौधरी हत्याकांड की जांच

नमस्ते राजस्थान

जोधपुर। अनीता चौधरी की हत्या जोधपुर में बीते कई दिनों से चल रहा धरना आज समाप्त हो गया है। सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने पर सहमति दे दी है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार ने बताया कि सरकार इस मामले में सीबीआई को चिढ़ी लियेगी। गौरतलब है कि सोमवार को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में बड़ा धरना दिया गया था, जिसमें अनीता चौधरी केस की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई थी। मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर सहमति बनने के बाद अनीता चौधरी के परिजनों का धरना भी समाप्त हो गया है। सरकार ने अनीता चौधरी के परिजनों को 51 लाख रुपये की



आर्थिक सहायता दिए जाने का भी ऐलान किया है। जोधपुर की बहुचर्चित अनीता हत्याकांड मामले मामले में मंगलवार 19 नवंबर को 20 दिन बाद धरना समाप्ति की घोषणा हुई। हनुमान बेनीवाल के धरना स्थल पर पहुंचने के साथ ही वहां हजारों की भीड़ जुट गई। इसके बाद आनन-फानन में प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर परिजनों की मांग पर सहमति दी। सरकार की ओर से अधिकारी और ओरिसिया विधायक भैराराम सियोल ने लोगों से बात की, जिसके बाद चार मांगों पर सहमति बनी।

शिक्षा मंत्री दिलावर बोले, सरकारी स्कूल में दो करोड़ का करो दान, स्कूल होगा आपके नाम

नमस्ते राजस्थान

जयपुर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि राजस्थान में कोई भी बच्ची फर्श पर बैठकर न पड़े यह हमारा विजन है और इसको साकार करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बालिका शिक्षा पर हमारा विशेष जोर है। शिक्षा मंत्री दिलावर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में द कॉन्क्लेव होटल में प्रवासी राजस्थानी परिषद द्वारा आयोजित एक कदम शिक्षा की ओर कार्यक्रम में बोल रहे थे। दिलावर ने कहा कि सरकार हर स्तर पर सहयोग और समर्थन करने को तैयार है। गत वर्ष में प्रदेश में 138 थामाशाह ने शिक्षा विभाग में एक हजार करोड़ से अधिक का निवेश किया। यदि कोई दानदाता 2 करोड़ से अधिक रुपए स्कूल में निवेश करते हैं तो स्कूल का नाम आपके नाम पर किया जाने की सरकार की योजना है। दिलावर ने कहा कि आप अपनी सुविधा अनुसार स्कूल गोद लेकर भी अपना योगदान दे सकते हैं। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजींग राजस्थान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिससे जुड़कर आप राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करने में सहायगी बन सकते हैं। पूरे देश विदेश में मारवाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। और आपके अपनी मातृभूमि से जुड़ाव भी है।

प्रदेश में 303 माइजर मिनरल ब्लॉकों की सफल ई-नीलामी, मिलेगा 374 करोड़ का राजस्व

नमस्ते राजस्थान

जयपुर। मुख्यमंत्री व खान मंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में भारत सरकार के ई-पोर्टल पर 34 मेजर मिनरल ब्लॉकों की सफल नीलामी कर राजस्थान समूचे देश में पहले स्थान पर आ चुका है। अब तक 303 माइजर मिनरल ब्लॉकों की सफल ई-नीलामी की जा चुकी है। इससे राजस्थान सरकार को 374 करोड़ 98 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

प्रीमियम की 40 प्रतिशत की पहली किश्त का राजस्व मिला

प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने बताया है कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13 नवंबर,



खुशखबर

2024 तक 303 माइजर मिनरल ब्लॉकों की सफल ई-नीलामी की जा चुकी है। इससे राज्य सरकार को प्रीमियम के रूप में तीन किश्तों में 374 करोड़ 98 लाख रुपए

का राजस्व प्राप्त होगा। प्रीमियम की 40 प्रतिशत की पहली किश्त के रूप में राज्य सरकार को 149 करोड़ 99 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

वैध खनन को बढ़ावा देकर राजस्व व रोजगार में बढ़ोतरी है टारगेट

प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशन में विभाग द्वारा मेजर और माइजर मिनरल के अधिक से अधिक ब्लॉक तैयार कर ऑक्शन करने पर बल दिया जा रहा है ताकि अवैध खनन पर रोक और वैध खनन को बढ़ावा देकर राजस्व व रोजगार में बढ़ोतरी हो सके।

अतिम चरण में हैं करीब 250 माइजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन की तैयारी

प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि माइजर मिनरल में मार्बल, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, सोप स्टोन, सोप स्टोन, क्लेसाइट, क्ले, रेड

सर्वाधिक 422 माइजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी वर्ष 21-22 में हुई

निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि पिछले आठ साल में सर्वाधिक 422 माइजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी 21-22 में हुई थी। इस साल माइजर मिनरल ब्लॉक तैयार किया गया। फिर ऑक्शन का रोडमैप तैयार कर कार्रवाई आरंभ की गई। जिसका परिणाम है कि मेजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन की तरह ही माइजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी का भी नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा।

ऑकर, क्वार्ट्स-फेल्सपार आदि आदि मिनरल आते हैं। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 709 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के 303 ब्लॉकों का सफल ऑक्शन भारत सरकार के ई-पोर्टल के माध्यम से किया जा चुका है। 190 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 120 माइजर मिनरल ब्लॉकों की ऑक्शन प्रक्रिया जारी है। वहीं 250 से अधिक माइजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन की तैयारी अतिम चरण में हैं।

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस

उदारतापूर्वक दान देकर सशस्त्र बलों के प्रति करे गहरी कृतज्ञता

नमस्ते राजस्थान

भीलवाड़ा, सशस्त्र सेना झण्डा दिवस (झंडा दिवस) भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण हेतु सन 1949 से प्रतिवर्ष 07 दिसम्बर को मनाया जाता है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया कि युद्ध के समय हुए जान-माल की हानि के बाद देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि वो अपने सैन्य कर्मियों, उनके परिवार के कल्याण के कार्यों में सहयोग करें। हम सभी को हमारे शूरवीरों की कीर्ति गाथाओं पर गौरव है। जिन्होंने 1947-48, 1962, 1965, 1971 व 1999 के युद्धों व आंतरिक संघर्ष में बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मन व आतंकवादियों के घुटने टिका दिये। उन्होंने बताया कि देशवासियों द्वारा दिया गया दान देश सेवा में अशक्त हुए सैनिकों, शहीदों एवं उनके परिवारजनों के कल्याण हेतु काम आता है। उन्होंने इन शूरवीरों एवं शहीदों के परिवार जनों के लिए सभी सर्वविधित परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर प्रदेश में संचालित विभिन्न प्राईवेट संस्थानों, युनिवर्सिटीज, स्कूलों के संचालकों एवं कॉरपोरेट क्षेत्र के सभी दानदाताओं एवं प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे उदारतापूर्वक दान देकर सशस्त्र बलों के प्रति हम सब गहरी कृतज्ञता अभिव्यक्त करें। दान जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में उपस्थित होकर या जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के नाम से डी०डी०/ बैंक के माध्यम से एवं विभाग के क्यूआर स्कैनर के माध्यम से भी किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु इच्छुक पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से आवेदन प्रस्ताव आमंत्रित

भीलवाड़ा, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों के लिये आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से उत्कृष्ट ढंग से कराने हेतु योजनान्तर्गत सूचीबद्ध होने के लिये इच्छुक पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं के आवेदन प्रस्ताव सत्र 2024-25 के लिये आमंत्रित किये जाते हैं।

सांस अभियान के पोस्टर का सीएमएचओ डॉ० गोस्वामी ने किया विमोचन

बच्चों को निमोनिया बीमारी के बचाव के लिए करेंगे जागरूक



नमस्ते राजस्थान

भीलवाड़ा, चिकित्सा विभाग द्वारा जिले में बच्चों में निमोनिया से बचाव, रोकथाम एवं उपचार पर कार्य करते हुए सांस (सोशल अवेयरनेस एण्ड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुल) अभियान की शुरुआत की गयी है। यह अभियान आगामी 28 फरवरी, 2025 तक आयोजित किया जायेगा। अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के संबंध में मंगलवार को सीएमएचओ डॉ. चेतेंद्र पुरी गोस्वामी व जिला आरसीएच अधिकारी डॉ. संजीव शर्मा ने सांस अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेंद्र पुरी गोस्वामी ने बताया कि देश में 5 वर्ष तक के बच्चों में निमोनिया एवं उससे होने वाली जटिलता बच्चों में होने वाली मृत्यु का एक मुख्य कारण है। सांस (सोशल अवेयरनेस एण्ड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुल) अभियान के दौरान जिले में स्वास्थ्य केन्द्रों पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर आमजन को निमोनिया के बारे में जागरूक किया जायेगा तथा 5 वर्ष तक समस्त बच्चों की निमोनिया की स्क्रीनिंग की जायेगी। अभियान को सफल बनाने के लिए चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को जिला स्तर से निर्देश दिये गये हैं।

निमोनिया के लक्षण:- यदि बच्चों में खांसी और जुखाम का बढ़ना, तेजी से सांस लेना, सांस लेते समय पसली चलना या छाती के अन्दर धंसना, तेज बुखार का आना जैसे लक्षण दिखाई दे, तो यह निमोनिया हो सकता है। इस स्थिति में तत्काल नजदीकी चिकित्सालय में बच्चे की जांच एवं पूर्ण उपचार करवाएं।

शहर के गणमान्य पाषंदों ने अधिशाषी अधिकारी को पत्र दिया बोर्ड की मितिंग बुलाने का

सरकार ने प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त कर दिया अब मितिंग बुलाने की याद कैसे आई

नमस्ते राजस्थान

शिवगंज नगर पालिका पाषंद बीजेपी व निर्दलीय ने बोर्ड की साधारण बैठक बुलाने की मांग की अधिशाषी अधिकारी को पत्र दिया जनप्रतिनिधि ने बोर्ड की बैठक 1 वर्ष में अधिक से अधिक या छह बार मितिंग होनी चाहिए लेकिन आज तक बोर्ड की बैठक नहीं बुलाकर कमेटी की बैठक बुलाने से पाषंदों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है समय से बोर्ड की बैठक नहीं होने के विकास की कार्यों में रुकावट आ रही है शहर विभाजन किया गया है कि खौंचा भूमि पत्रावली विचार विमर्श 69क के पट्टे निस्तारण करने बाबत पुराने पालिका भवन पर विचार विकास कार्य करवाने बाबत क्या इन पाषंदों ने लिखकर दे दिया भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष को पता होना चाहिए अब बोर्ड समाप्त हो चुका है आज का दिन लास्ट है फिर यह नौटंकी करने की कहां जरूरत इन्होंने लिखित में दिया पत्र से साफ जाहिर होता है कि सुमेरपुर वालों ने पत्र देकर मितिंग बुलाई जो आज संपन्न हो गई सब जगह बुलाई गई



नगर पालिका अध्यक्ष ने तो बिल्कुल ही बोर्ड की बैठक नहीं बुलाने की कसम खाई हो इन्होंने सिर्फ पूर्व विधायक के कहने पर ही मितिंग बुलाई गई थी वह जिस मितिंग में पूर्व विधायक उपस्थित

होते थे वही मितिंग होती थी बाकी निरस्त हो जाती थी कमेटी मितिंग में खूब घोटाले किए खूब भ्रष्टाचार किया पर विपक्ष चुप बैठा रहा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद भी भारतीय

जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष वह पाषंद चुप बैठे थे इसका मतलब क्या इनको पता है शिवगंज नगर पालिका में सैकड़ों पट्टे फर्जी बने अवैध काम हुए उनका पता नहीं इतनी अखबारों में

आने के बाद भी इन्होंने कोई शिकायत नहीं की नहीं करवाई करने का लिखा क्योंकि नगर मंडल अध्यक्ष खुद के नाम के प्लॉट अभी दे वह क्या शिकायत करेंगे सब बंदे हुए हैं पालिका अध्यक्ष के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है ऐसे ही चल रहा तो भारतीय जनता पार्टी की शहरी सरकार आगे नहीं बनेगी शहर की जनता दुखी है जगह-जगह पर खड़े हुए पानी की समस्या है इतनी समस्या होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं करवाना मतलब राजस्थान के राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी नहीं सुन रहे क्या जनता के साथ कुठाराघात हो रहा है अगर यह पाषंद एक्टिव होते तो इनको 10 दिन पहले पत्र भेजने कलेक्टर को मितिंग बुलाने का अधिकार कलेक्टर को है अगर पालिका अध्यक्ष नहीं सुनते हैं तो इन्होंने तो वह भी टाइम पूरा कर दिया क्या जरूरत थी पत्र देकर जनता को बताने की कि हम जनता के साथ फजीवाड़ा करना आता है नगर मंडल अध्यक्ष को अब अपना काम निकाला है जनता व भाजपा के कार्यकर्ताओं का सब परेशान है।

अवैध खनन को लेकर प्रशासन सख्त, जीरो टॉलरेंस की नीति अपना की जा रही कारवाई

विशेष अभियान के तहत प्रथम दिन जिले में कुल 9 प्रकरण बनाकर 9 वाहन और 37 टन बजरी जब्त



25 नवंबर तक चलेगा विशेष अभियान

03 प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज

नमस्ते राजस्थान

भीलवाड़ा, जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है, जिसमें जीरो टॉलरेंस



की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। यह अभियान 25 नवंबर तक चलेगा, जिसके तहत पहले दिन ही 9 प्रकरण दर्ज कर 9 वाहन और 37 टन बजरी जब्त की गई है। इसके अलावा, तीन प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। खनि अभियंता चंदन कुमार ने बताया कि अभियान के प्रथम दिन जिले के

बीगोद में अवैध बजरी परिवहन कर रहे बजरी से भरे 2 ट्रेक्टर ट्रॉली एवं थाना मांडलगढ़ में पिथा जी का खेड़ा के पास अवैध बजरी परिवहन कर रहे बजरी से भरे 1 ट्रेक्टर ट्रॉली को खनिज बजरी का अवैध निर्गमन करते हुए जब्त किया गया। तीनों प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। साथ ही आसीद, गुलाबपुरा और रायपुर

में 2 ट्रेक्टर ट्रॉली खनिज बजरी का अवैध निर्गमन करते हुए जब्त किए गए। इस संबंध में अभियान की क्रियान्विति के लिए जिला कलक्टर श्री नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने सोमवार को जिला कलेक्टर के वीसी कक्ष से बैठक लेकर जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों, पुलिस विभाग के अधिकारियों तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। बैठक के दौरान जिला कलक्टर ने अवैध खनन, निर्गमन तथा भण्डारण की रोकथाम के लिए अधिकारियों को अवैध खनन के विरुद्ध जीरो टोलरेंस रखते हुए अधिकाधिक कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

जिला कलक्टर नमित मेहता के नेतृत्व में शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान की हुई शुरुआत

शहर को अतिक्रमण मुक्त, स्वच्छ और सुंदर बनाने में शहरवासी दे सहयोग: जिला कलक्टर

नमस्ते राजस्थान

भीलवाड़ा, जिला कलक्टर नमित मेहता के निर्देशन में शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान की शुरुआत मंगलवार से की गई। अभियान के प्रथम दिन शाम तक अजमेर चौराहा से आरजिया चौराहे के बीच सड़क के एक तरफ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस मुख्य मार्ग पर से बाकी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बुधवार को पूरी की जाएगी।

रोजाना निगरानी के लिए टीम गठित

नगर निगम आयुक्त हेमराम चौधरी ने बताया कि शहर में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए अभियान के पहले दिन कई महत्वपूर्ण कार्यवाहियों की गईं। प्रथम दिन अभियान में लगभग 37 दुकानों के टीन शेड हटाए गए, जो सड़कों और गलियों में अतिक्रमण कर रहे थे। इसके साथ 5 केबिन भी हटाने की कार्रवाई भी की गई। इसके अलावा 18 दुकानों और प्रतिष्ठानों

अभियान के प्रथम दिन 37 दुकानों के टीन शेड हटाए, 18 दुकानों और प्रतिष्ठानों द्वारा फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण सहित 5 अवैध केबिन को हटाया



द्वारा फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया। इस व्यवस्था को कायम रखने के लिए निगम की एक टीम बनाई है जो रोज दिन में राउंड लेगी। अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम, यूआईटी, प्रशासन, पुलिस की संयुक्त टीमें सुबह 11 बजे से पुलिस जाबों के साथ पहुंची। इस दौरान पहले से मार्किंग किए अतिक्रमण को सबसे पहले हटाया गया। दुकानों के मूल आकार से

ज्यादा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

जिला कलक्टर की आमजन से अपील

जिला कलक्टर नमित मेहता ने कहा कि यह अभियान शहर को अतिक्रमण मुक्त कर शहर की सड़कों को सुगम और सुंदर बनाने के लिए शुरू किया गया है। मुख्य मार्गों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के साथ ही यह पहल शहर

के यातायात की समस्याओं को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि लोग शहर को अतिक्रमण मुक्त, स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करें। गौरतलब है कि जिला कलक्टर नमित मेहता ने शहर की ट्रैफिक समस्या को देखते हुए बैठक लेकर भीलवाड़ा की प्रमुख सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए थे। इसी की पालना में अभियान की शुरुआत की गई। नगर निगम, यूआईटी, प्रशासन, पुलिस की टीम ने संयुक्त निरीक्षण कर व्यापारियों को समझाया और इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर हेमराम चौधरी, यूआईटी तहसीलदार नीरज रावत, ट्रैफिक सीओ सुरेश, एक्सईएन जीतराम जाट, एईएन रामप्रसाद जाट, जेईएन रुचि अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

पूर्व विधायक ने झूठी वाह वाह लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी



पुलिया निर्माण की जाँच कर दोषी अधिकारीओ के विरुद्ध कार्रवाई करावे

नमस्ते राजस्थान

शिवगंज पुलिया निर्माण हो रहा पुलिया निर्माण कार्य किया जा रहा वह राजस्व रिकार्ड में तरमीम रास्ते पर नहीं करवा कर जिस स्थान पर निर्माण कार्य किया जा रहा है उस स्थान का एक भाग जो श्री गौतम ऋषि महादेव मंदिर को जोड़ने वाला पुलिया का एक स्पेन (रखल्ल) एवं पुलिया अबर्टमेंट दिवार एवं एप्रोच सड़क वन विभाग की सीमा एवं भूमि में आता है जिसकी वन विभाग से कोई सक्षम स्तर की अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया और इस कार्य का तकमीना वन विभाग सिरोही की बिना जानकारी के तत्कालीन अंतरिम प्रबंध कमेटी एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग सिरोही द्वारा बनाया है एवं जो निर्माण कार्य करवाया गया है वह अवैध है एवं वन विभाग सिरोही द्वारा कार्य प्रारम्भ करवाते समय ही रुकवाया गया उसके उपरान्त भी कार्यकारणी एजेन्सी एवं तत्कालीन अंतरिम प्रबंध कमेटी द्वारा वन विभाग पर दबाव बनाकर मोखिक स्वीकृति अनुसार कार्य करवाया जा रहा है इसी प्रकार दूसरा निर्माण कार्य सबमर्सिबल पुलिया निर्माण चोटिला भागली के पास नदी पर बनाया जा रहा है यह चोटिला भागली को जोड़ने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तकमीना बनाकर कार्य करवाये जा रहे हैं जो नियम विरुद्ध मूल स्वीकृति स्थल से लगभग एक किलोमीटर दूरी पर नियम विरुद्ध करवाया जा रहा है जहां



पूर्व में रपट का निर्माण किया हुआ है। मीणा ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गयी घोषणा एवं निर्माण कार्य का मीणा समाज के लोगो ने कई बार राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन को ज्ञापन दिये एवं उपखंड कार्यालय शिवगंज पर विरोध प्रदर्शन किये यहां तक मीणा समाज के लोगो ने एवं वन विभाग द्वारा भी उक्त कार्यों को रुकवाया गया परन्तु सार्वजनिक विभाग सिरोही एवं तत्कालीन अंतरिम प्रबंध समिति की मिली भगत एवं हठधर्मिता से यह अवैध निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं एवं मीणा समाज के लोगो के विरुद्ध को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मीणा पुलिस थाना पालड़ी एम. राज कार्य में बांधा डालने का मुक्कदमा भी दर्ज करवाकर समाज के लोगो पर दबाव बनाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं तत्कालीन अंतरिम प्रबंध समिति मिलकर सरकारी राशि हड़पने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है कार्यकारी एंजेसी सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं प्रस्ताव देने वाली तत्कालीन अंतरिम प्रबंध समिति द्वारा नियम विरुद्ध प्रस्ताव बनाकर करवाये गये निर्माण कार्यों को रुकवाकर अब तक व्यय की गयी राशि वसूल कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की।

काम्प्लैक्स का विवादों से नाता है पहले एक महाराज ने दादागिरी की थी फिर पालिका प्रशासन ने सीज किया है

अब इसका कोरनर की बिल्डिंग होने से कोरनर नहीं काटा है बड़ा विवाद होगा

शहर में बड़ा आंदोलन होगा की ओपन लैण्ड भूमि पर सिर्फ पार्किंग होनी चाहिए सभी दुकानों को हटाने तक आंदोलन होगा

बिल्डर ने अंडर ग्राउंड पार्किंग की जगह दुकाने बेवी हुई है अब सबको उपर ग्राउंड फ्लोर में दुकाने देनी पड़ेगी

अब खुद के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए तब मालिक के विरुद्ध कारवाई की मांग करेंगी जनता तब क्या होगा

बिल्डर्स से धोखाधड़ी पूर्वक एंटे करोड़ों रूपए, नहीं करवाई रजिस्ट्री, थाने में दी रिपोर्ट

नमस्ते राजस्थान

शिवगंज। शहर के महाराजा मैदान के सामने निर्माणाधीन व्यवसायिक काम्प्लैक्स का विवादों से नाता है जो आए दिन हो रहा है पहले पार्किंग अब उपरी दुकाने फिर अंडर ग्राउंड में पार्किंग होनी चाहिए फिर कौन कारवाई करेगा वह अब भवन के मालिक के साथ कथित रूप से करोड़ों रूपए एंठने के बाद भी भूमि की रजिस्ट्री नहीं करवाने और रजिस्ट्री करवाने के एवज में पांच करोड़ रूपए और मांगने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर अपना सब कुछ गवां बैठे बिल्डर्स ने उसके साथ हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट पुलिस थाने में देकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है पुलिस को दी रिपोर्ट में सर्व शिव डवलपर्स एंड ट्रेडिंग कंपनी के मालिक हीरालाल माली ने बताया कि उसकी फर्म आवासीय-व्यवसायिक भूमि का विकास एवं निर्माण का कार्य करती है। रिपोर्ट में बताया कि उसने सुभाष नगर में स्थित एक 4683.25 वर्ग फीट भूमि जिसमें 2901.75 वर्गफीट भूमि ओम इन्फ्रास्ट्रक्चर के साझेदार ओमप्रकाश खंडेलवाल, जयेंद्र कुमार सोनी, नरेश टेकवानी तथा महिपालसिंह चौहान सभी निवासी सिरोही की थी, शेष भूमि का मालिकाना हक राहुल गांधी एवं राजकुमार लाखोटिया निवासी सुमेरपुर के नाम से थी। रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2020 में इन लोगों ने उनके कार्यालय आकर संपर्क कर अच्छा मुनाफा कमाने प्रस्ताव और अन्य लुभावने प्रलोभन दिए कि आप इस भूमि को हमसे खरीद कर पूरी भूमि पर वाणिज्यिक काम्प्लैक्स का निर्माण कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा मुनाफा होगा। चार करोड़ सोलह लाख में तय हुआ सौदा रिपोर्टकर्ता ने बताया कि इन लोगों की लुभावनी बातों में आकर उसने दो अलग अलग भूमि में से एक का सौदा 1 करोड़ 60 लाख में तथा



दूसरी का सौदा 2 करोड़ 56 लाख में तय करते हुए इकरारनामा इस शर्त के साथ तैयार किया कि तय की गई संपूर्ण राशि का भुगतान दो वर्ष में होने के बाद भूमि की रजिस्ट्री करवा दी जाएगी। सौदा तय हो जाने के बाद प्रार्थी ने दोनों को अलग अलग 3 लाख 40 हजार तथा 51 हजार रूपए साईं पेटे देकर भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया। इसके अगले दिन ही दोनों पक्षों के साथ मुख्तियारनामा तैयार करवाया गया ताकि प्रार्थी व्यवसायिक भवन का निर्माण करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों से अनुमति, लाइट बिजली का कनेक्शन लेने और निर्माण का कार्य कर सके सौदे के अनुसार राशि देने के बाद भी कर दी धोखाधड़ी रिपोर्ट में प्रार्थी हीरालाल ने आरोप लगाया कि अप्राथियों से जिस इकरारनामे के आधार पर सौदा किया गया था। उसके तहत समय समय पर व्यवसायिक भवन की दुकानें बेचने के समय तक तय राशि का भुगतान कर लिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपियों ने गहरी साजिश रचते हुए जिस भूमि का सौदा उसके साथ हुआ था उसमें धोखाधड़ी करते हुए ओम इन्फ्रास्ट्रक्चर के



साझेदार ओमप्रकाश खंडेलवाल व यमुना कुमारी के पक्ष में कर दिया। रिपोर्ट में बताया कि उसने आरोपी ओमप्रकाश वगैरह को उनकी जमीन के पेटे अब तक 3 करोड़ 79 लाख रूपए का भुगतान कर दिया है, जो तयशुदा प्रतिफल से 1 करोड़ 23 लाख रूपए ज्यादा है। बावजूद उसके पक्ष में रजिस्ट्री नहीं करवाई जा रही है सोचे समझे षडयंत्र में फंसाने का आरोप रिपोर्टकर्ता ने बताया कि आरोपियों ने इतनी बड़ी धनराशि ऐठने के बाद भी उसके पक्ष में रजिस्ट्री नहीं करवाई जिससे उसे आर्थिक एवं मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी। इतना ही नहीं उसका बैंक में एक



ऋण खाता भी एनपीए हो गया। जिससे रियल स्टेट मार्केट में उसकी छवि धूमिल हो गई। इतना ही नहीं वाणिज्यिक परिसर में इतना बड़ा निवेश करने के बाद भी उसे इसका लाभ नहीं मिल पाया। रिपोर्टकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने साजिश कर उससे पैसा ऐठने का सोचा समझा षडयंत्र रचा और उसमें उसे ऐसा फंसाया कि वह इससे कभी बाहर ही नहीं आ सका। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि इन आरोपियों ने उसके जैसे ही और भी कई लोगों को बहला फुसलाकर निवेश के नाम पर पैसे दबा रखे हैं और उन्हें भी डरवाया धमकाया जा रहा है। रिपोर्टकर्ता ने पुलिस को बताया

कि अब आरोपियों की ओर से उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस मामले को लेकर प्रार्थी ने आरोपियों को तीन लीगल नोटिस भी भेजे हैं, जिसका जवाब भी उन्होंने आज तक नहीं दिया है। रिपोर्ट में आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
क्या अब इस सर्व शिव काम्प्लैक्स की पार्किंग की जगह दुकाने हटाई जाएंगी
ईस काम्प्लैक्स में अंडर ग्राउंड पार्किंग की जगह पर बनाई दुकानों को हटाय जाएगा या उच्च न्यायालय का सहारा लेकर पार्किंग की जगह पर पार्किंग होनी चाहिए तब जाकर शिवगंज शहर की जनता को न्याय मिलेगा अन्यथा पालिका प्रशासन ने फजीवांदा करने के लिए सीज की कार्रवाई की है सिर्फ धन लेकर खोल देंगे सीज तो पार्किंग की जगह पर बनाई दुकानों के मालिक व कर्मचारियों की गाड़ियाँ कहीं जाएंगी वह सडकों पर पड़ी रहेगी जिससे दुर्घटना होने की पुरी सम्भावना है रिपोर्टकर्ता कोन लेगा क्या उपखंड अधिकारी पालिका प्रशासन या पुलिस प्रशासन कारवाई करेंगी देखते हैं या सभी धन के बल पर अंडर ग्राउंड में पार्किंग रहेंगी देखते हैं आगे क्या होता है।

पुलिस की गाड़ी में बैठ बनाई रील, सोशल मीडिया पर की अपलोड; हाईवे पेट्रोलिंग टीम की थी जीप, एसपी ने पूरी टीम को हटाया

नमस्ते राजस्थान

बाड़मेर बाड़मेर पुलिस की जीप में बैठकर एक व्यक्ति ने रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इधर, जैसे ही ये वीडियो एसपी तक पहुंचा, उन्होंने हाईवे पेट्रोलिंग की पूरी टीम को लाइन हाजिर कर दिया। मामला मंगलवार का है, हालांकि ये वीडियो कब बनाया गया और कब अपलोड किया गया था, इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। ये भी दावा किया जा रहा है कि रील बनाने वाले व्यक्ति बजरी माफियाओं से जुड़ा है। पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। मामले की जांच गुडामालानी डिप्टी सुखराम विरनोई को सौंपी गई है।

पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग जीप में उतरते हुए बनाई रील

दरअसल, जिस पुलिस गाड़ी में रील बनाई है वह हाईवे पेट्रोलिंग टीम की है। वीडियो नेशनल हाईवे 68 बाड़मेर-सांचौर रोड का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति पुलिस जीप से एक्शन में नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया- वीडियो कब बना है और कब अपलोड हुआ है इसकी जांच की जा रही है। मंगलवार सुबह ये वीडियो हमारे पास पहुंचा था। इसके बाद मामले की जांच शुरू की है। प्रारंभिक तौर पर पेट्रोलिंग टीम के एक इन्सपेक्टर, हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। उन्होंने बताया- अभी तक जांच में सामने आया है कि गाड़ी खराब हो गई थी और इसे ठीक करवाने रुके थे। इसी दौरान ये वीडियो बना लिया।

ऑफिशियल केडी कड़वासा 46 आईडी पर की थी अपलोड

जानकारी के अनुसार रील इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल केडी कड़वासा 46 आईडी पर अपलोड की गई थी। 14 सेकेंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है। हालांकि मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया अकाउंट से इस रील को डिलीट कर दिया गया है।

जयपुर में क्रेटा से आए बदमाश स्कॉर्पियो चुरा ले गए: एक चोर घर के बाहर से ले गए गाड़ी, 48 मिनट में वारदात को अंजाम दिया

नमस्ते राजस्थान

जयपुर जयपुर के श्याम नगर थाना इलाके में देर रात 48 मिनट में एक बदमाश स्कॉर्पियो कार चोर कर फरार हो गया। कार चोरी की जानकारी मिलने पर कार मालिक अशोक शेखावत ने श्याम नगर थाना पुलिस को जानकारी दी। इस पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इलाके में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एक जगह पर पुलिस को वारदात करने वाले आरोपी का वीडियो मिला, लेकिन चेहरा छुपा हुआ था। पीड़ित अशोक शेखावत ने बताया- वह अपने परिवार के साथ निर्माण नगर स्थित घर में थे। उनकी स्कॉर्पियो कार घर के सामने खड़ी थी। रात करीब 3.10 बजे चोर घर के बाहर खड़ी कार चोरी कर फरार हो गया। सुबह सवा 7 बजे जब परिवार उठा तो देखा की कार घर के बाहर खड़ी नहीं है। इस पर घर के सीसीटीवी फुटेज देखे गए जिस से पता चला की रात करीब 2.32 बजे क्रेटा कार से चार से पांच बदमाश आए थे। कार से एक बदमाश बाहर निकला। उस के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। आरोपी ने कार का सेंट्रल लॉक तोड़ा और कार को करीब 3.18 बजे फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस श्याम नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। इलाके में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी।

प्रियंका गांधी 3 दिन करेंगी टाइगर सफारी: पति, बेटा-बेटी व सास भी है साथ, परिवार के साथ छुट्टियां मनाने पहुंचीं रणथंभौर

नमस्ते राजस्थान

सवाई माधोपुर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा एक बार फिर रणथंभौर में छुट्टियां मनाने पहुंचीं हैं। मंगलवार दोपहर को प्रियंका गांधी वाड़ा पूरे लवाजमे के साथ रणथंभौर पहुंचीं। वह यहां एक पांच सितारा होटल में रुकी हैं। इस दौरान यहां पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम देखने को मिले हैं। वायनाड चुनाव के बाद मंगलवार को दोपहर करीब 12:30 बजे कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड़ा अपनी सास मोरिन वाड़ा, पति रॉबर्ट वाड़ा, बेटा रेहान वाड़ा, बेटी निराया वाड़ा के साथ रणथंभौर पहुंचीं। सभी लोग यहां तारा होटल शेरबाग में ठहरे हुए हैं। इस दौरान इनका यहां पर रणथंभौर में टाइगर सफारी करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।
रणथंभौर में सेलिब्रेट कर चुकी हैं प्रियंका
जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी वाड़ा 5 दिन के राजस्थान तैर पर आई हुई हैं। जिसमें से 3 दिन वह सवाई माधोपुर में रुकेगी। इस दौरान वह रणथंभौर में सुबह और शाम की पारी में टाइगर रिजर्व में सफारी का आनंद लेंगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी प्रियंका गांधी वाड़ा रणथंभौर में अक्सर आती रही हैं। वह अपना बर्थडे भी रणथंभौर में सेलिब्रेट कर



चुकी हैं। वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी अपने भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी के साथ होटल शेरबाग में ही रुकी थीं।
600 करोड़ रूपए का टूरिज्म अकेले टाइगर से
रणथंभौर टाइगर रिजर्व: यह देश के सबसे

लोकप्रिय टाइगर रिजर्व में से एक है, जो न केवल टाइगर बल्कि अन्य वन्यजीवों के लिए भी एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। साल 2024 में यहां से लगभग 600 करोड़ रूपए का राजस्व होने की उम्मीद है।
जवाई बेरा कंजर्वेशन रिजर्व: यहां 50 से

अधिक लेपर्ड हैं। यह क्षेत्र अपनी अनोखी लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध है। इसका अनुमानित राजस्व करीब 150 करोड़ रूपए है।

एक अक्टूबर से शुरू हुआ टूरिज्म सीजन

रणथंभौर में एक अक्टूबर से टूरिस्ट सीजन शुरू हुआ है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में कुल 10 जोन हैं। इनमें 2 पारियों में टाइगर सफारी होती है। सुबह 7 की पारी में सफारी सुबह 6 से 9 बजे तक होती है। शाम की रिफ्ट में सफारी दोपहर तीन बजे से शाम 6 बजे तक होती है। रणथंभौर में फिलहाल 75 बाघ, बाघिन और शावक हैं।

प्रियंका गांधी ने किताब में किया जिक्र

पिछले 12 साल से प्रियंका गांधी अपने दोनों बच्चों के साथ हर साल रणथंभौर पार्क में आ रही हैं। वे अब तक हजारों फोटो यहां के टाइगर की खींच चुकी हैं और उन्होंने एक किताब में भी रणथंभौर के बाघों का जिक्र किया है। प्रियंका इस साल भी अप्रैल में यहां आई थीं। प्रियंका के बेटे रेहान वाड़ा ने तो रणथंभौर से खींचे फोटोज की एक प्रदर्शनी भी लगाई थी और प्रियंका गांधी ने एक किताब की 191 पृष्ठ लिखी है। हिंदी में इसे बाघ की राजधानी कहते हैं।

राजीव गांधी के नाम पर होता रणथंभौर पार्क

रणथंभौर पार्क पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी बेहद पसंद था। वे सोनिया गांधी से शादी के तुरंत बाद रणथंभौर आए थे। इसके अलावा भी वे यहां कई बार आए। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए रणथंभौर के लिए कई काम कराए। साल 1998 से 2003 के बीच अशोक गहलोट पहली बार राजस्थान के उट बने तो उन्होंने रणथंभौर नेशनल पार्क का नाम राजीव गांधी के नाम पर करने की मांग जाहिर की, लेकिन विपक्षी पार्टी भाजपा की ओर से विरोध जताए जाने पर विवाद से बचने के लिए गहलोट ने अपना इरादा टाल दिया था।
रणथंभौर में 75 टाइगर
रणथंभौर नेशनल पार्क 1700 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहां 75 बाघ, बाघिन और शावक हैं। एक बाघ को लगभग 35 किलोमीटर टैरेटरी की आवश्यकता होती है। ऐसे में यहां 50 बाघ रह सकते हैं। यानी रणथंभौर में 25 बाघ-बाघिन क्षमता से अधिक हैं।
राजस्थान में 100 से ज्यादा टाइगर
राजस्थान में वर्तमान में टाइगर की संख्या 100 से ज्यादा है। देश भर में इनकी संख्या करीब 3200 है। राजस्थान की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि राजधानी जयपुर सहित 1970-72 तक राज्य के लगभग 17 जिलों में टाइगर की मौजूदगी थी। यह मौजूदगी धीरे-धीरे घटती हुई 2005 में केवल एक ही जिले सवाई माधोपुर (रणथंभौर) तक सीमित रह गई। शेष सभी जिलों से टाइगर का सफाया हो गया। 2010 के बाद शुरू किए गए प्रयासों से आज फिर से यह स्थिति बनी है कि एक प्रदर्शनी भी लगाई थी और प्रियंका गांधी ने एक किताब का पैतृक घर रणथंभौर ही है। देश भर में लगभग 53 टाइगर पार्क हैं।

कोलोनी काटी रिको ने विकास किया पालिका ने

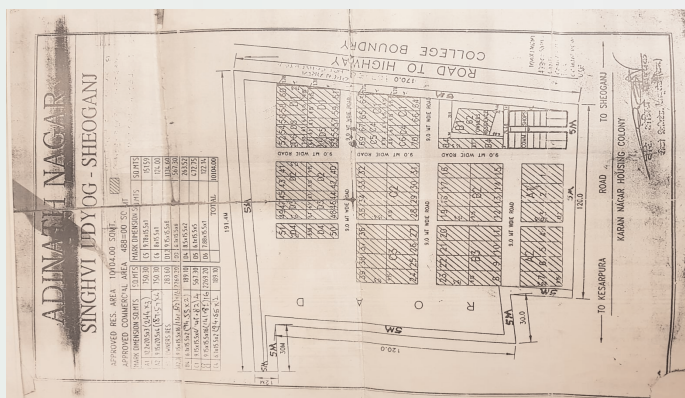
कोलोनी का साईड बैक व ओपन लैण्ड भूमि को बेचा गया है इसकी कारवाई क्यू नहीं हुई

सधवी उधोग के मालिक के विरुद्ध कानूनी कारवाई करे नक्शे स्वीकृत मे सडक की भूमि को बेचा गया बगीचा बनाने की माँग

पालिका प्रशासन ने इस कोलोनी मे विकास नियमों के विरुद्ध किया अधिकारी से वसूला जाएँ

नमस्ते राजस्थान

शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र में ऐसे तो आसपास में नगर पालिका का आवासीय क्षेत्र है उसी के बीच में एक टुकड़ा रिको का आया हुआ उसमें रिको आबूरोड द्वारा कोलोनी काटी गई थी उस कोलोनी में एक पार्टी द्वारा आम जनता को प्लाट बेचकर जनता के साथ बड़ा धोखा किया आदिनाथ नगर नाम से संघवी उधोग के नाम से एक सेठ लोग ने लोगों को प्लाट बेचकर करोड़ों रुपए कमा कर चला गया लोगों को सुविधा के लिए जो जमीन दी थी वह भी इस पार्टी ने बेच दी इसी के पास सड़क की भूमि को भी इस सेठ में बेच दी जो अब कुछ लोग इसमें प्लाट काट कर लोगों को गुमराह कर बेच रहे हैं रिको विभाग द्वारा इससे सेटिंग करके या धन लेकर इसकी रजिस्ट्री करवा दी क्योंकि इसकी रजिस्ट्री हो नहीं सकती थी इस प्लान के अंदर यह रोड की भूमि है वह इस कॉलोनी की साइड बैक की भूमि पर भी लोगों ने कब्जा कर दिया इस कॉलोनी में जितनी भी भूमि छोड़ी गई उन सब में शिवगंज के सेठ लोगों ने कब्जा कर दिया और अंदर निवास करने वाले लोगों के लिए नहीं तो बगीचे के लिए छोड़ा और नहीं सड़क की भूमि शिवगंज के एक धन्ना सेठ ने इस पर जो कॉलोनी में साइड बैक 5 मीटर छोड़ा गया था जो करीब 15 फिट से अधिक बनता है वह उससे अधिक उस पर भी उन्होंने कब्जा करके मकान बना दिया सरकारी जमीन पर बड़ा बगीचा बनाकर लोगों को किराए पर दे रहे हैं और किराया खा रहे इस



कॉलोनी के अंदर जितनी सड़क होनी चाहिए उतनी सड़क भी नहीं है और जो लास्ट में सड़क छोड़ी गई थी जो प्लान के अंदर भी आज रोड लिखा हुआ है उसको भी यह सेठ बेच कर खा गया जो इस कॉलोनी में खरीदने वाले लोगों के साथ धोखा किया इस सेठ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि इसने कॉलोनी काटने के बाद जो सुविधा होनी चाहिए वह रिकॉर्ड में होनी चाहिए क्योंकि पैसे वाला सेठ ने लिया था पर इस कॉलोनी का विकास पालिका प्रशासन शिवगंज ने किया जो सरकारी आदेशों की धजिया उड़ा कर इन्होंने इस कॉलोनी के अंदर रोड लाइट पानी लाइन वह सड़क

बनाई जो पालिका को करोड़ों रुपए का नुकसान किया यह पैसा इस कॉलोनी के मालिक से वसूल करना चाहिए क्योंकि यह सेठ लोग सरकारी प्रशासन को थोड़ा उसको भी यह सेठ बेच कर खा गया जो इस कॉलोनी में खरीदने वाले लोगों के साथ धोखा किया इस सेठ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि इसने कॉलोनी काटने के बाद जो सुविधा होनी चाहिए वह रिकॉर्ड में होनी चाहिए क्योंकि पैसे वाला सेठ ने लिया था पर इस कॉलोनी का विकास पालिका प्रशासन शिवगंज ने किया जो सरकारी आदेशों की धजिया उड़ा कर इन्होंने इस कॉलोनी के अंदर रोड लाइट पानी लाइन वह सड़क

चाहिए वह बच्चों के लिए गार्डन जरूरी है अंदर झूले वगैरा लगने चाहिए जिससे बच्चे खेल सकें और बुजुर्ग लोग शाम सुबह बगीचे में आकर बैठ सकें वह इस कॉलोनी मालिक को क्या पड़ी करोड़ों रुपए मिल रहे हैं जो जमीन पड़ी है उसको बेचकर खा रहे हैं उद्योग विभाग वाले इनके साथ मिले हुए हैं इसलिए उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग करती है शिवगंज की जनता व जनता के साथ धोखा कर यह लोग सुविधा की जमीन बेचकर खा रहे हैं इसका करोड़ों रुपए कमाए यह सब फजीर्वाड़ा करके इस कॉलोनी में जो सुविधा होनी चाहिए वह नहीं है इस जमीन पर बड़ा बगीचा बनना

क्षेत्र के अधीन है और नगर पालिका प्रशासन को भी इस मालिक के विरुद्ध कार्रवाई करवा कर जो भी जमीन है वह पालिका को देनी चाहिए या लेनी चाहिए वह इसके चारों तरफ जमीन पड़ी साइड बैक जो 5 मीटर से अधिक है जमीन कब्जा कर दिया तुरंत यह 5 मीटर जमीन खाली करवानी चाहिए तब जाकर इस कॉलोनी के सड़क चौड़े हो जाएंगे वह लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी और जिस सेठ ने सरकारी जमीन को बेची है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए तब जाकर इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों को न्याय मिलेगा और बगीचा बनने से बच्चे को बुजुर्गों को वह महिलाओं के लिए बैठने की सुविधा हो जाएगी तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए इनका क्या कहना है शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र के कोलेज के पास रिको विभाग ने एक वर्धमान कोलोनी निजी सेठ लोगों ने अपने फायदा लेने के लिए रिको और पालिका प्रशासन को गुमराह कर कोलोनी काटी गई कोलोनी की साइड बैक भूमि ओपन लैण्ड भूमि व रास्ते की भूमि भी इस सेठ ने लोगो को बेच दी कोलोनी स्वीकृत भी औद्योगिक रिको विभाग वालों ने की थी पर अब अंदर निवासियों के

साथ धोखाधड़ी की है क्यू की लोगो के जीवन में सब सुविधा चाहिए पर रिको औद्योगिक विभाग व सेठ ने मिलकर लोगो के साथ धोखाधड़ी की है पालिका प्रशासन ने रोड लाइट व सी सी सड़क का निर्माण भी करोड़ों रुपए खर्च करके बनाएँ यह पैसा औद्योगिक रिको विभाग वालों से या सेठ लोग से वसूला जाएँ अन्यथा पालिका प्रशासन अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी कनिष्ठ अभियन्ता से वसूला जाएँ जो लोगो के सुविधाओं के लिए छोड़ी जमीन को खुल्ला किया जाएँ तब आम लोगो के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी साइड बैक भूमि 15 मीटर छोड़ी है जो लाखों फिट है ओपन लैण्ड पर सेठ ने कब्जा कर लिया है जो अतिक्रमण हटाना चाहिए

ने सड़क बनाई नहीं लाइट लगवाई और नहीं पानी की व्यवस्था की यह तो पालिका प्रशासन ने सभी व्यवस्था की जो पालिका प्रशासन का धन खर्च हुआ वह इस संघवी उधोग वाले से यह धन वसूल करना चाहिए वह सड़क की जमीन खाली करवा कर इसने जो भी सड़क की भूमि बेची है उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए सड़क की जमीन को वापस कॉलोनी वालों के लिए सुविधा करना चाहिए तब जाकर कॉलोनी निवासियों को न्याय मिलेगा नहीं तो कॉलोनी निवासी उगा महसूस करेंगे खुद को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए व सधवी उधोग के मालिक से पैसा वसूल किया जाए जैसारांम माली अध्यक्ष जवाई पर्यावरण एवं वन विकास समिति शिवगंज इस रिको की कोलोनी की सड़क की जमीन बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की करनी चाहिए व शिवगंज नगर पालिका प्रशासन को जो खाली पड़ी जमीन अपने कब्जे में लेकर सधवी उधोग के मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए तब जाकर कोलोनी में निवास करने वाले लोगो को न्याय मिलेगा व भूमाफियाओ व भ्रष्टाचारीओ के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए कमलशिव चौहान समाजसेवी गौरक्षक शिवगंज

कामबेश्वरजी व कोलर जिस पंचायत मे आते है वहाँ पर हजारों बिधा गोचर भूमि है

गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर रिसोर्ट व आलिशान होटले बनाकर जानवरों के निवास करने की जमीन पर कब्जा कर लिया

जहाँ सबसे ज्यादा भालुओं व तेंदुओं के निवास क्षेत्र है वहाँ पर जिपसीओ की आवाज से परेशान किया जाता है

ईन पहाडियों में व आसपास गांवो से हजारो बिधा जमीन जो गोचर फौरेसट विभाग की जमीन पर अतिक्रमण को हटाना चाहिए

नमस्ते राजस्थान

शिवगंज उपखंड क्षेत्र के गोडाना धुरबाना पंचायत क्षेत्र के पहाडियों में सबसे ज्यादा गोचर भूमि आई हुई है वह उच्च गोचर भूमि में सबसे ज्यादा रिसोर्ट बने हुए है यह लोग गोचर को भी नहीं छोड़ते हैं तो फॉरेस्ट की भूमि को क्या छोड़ेंगे इसी के पास में फॉरेस्ट की लैंड भी आई हुई है जो अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे है उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा तो ध्यान देना ही उचित नहीं समझते तहसीलदार महोदय ऑफिस से बाहर नहीं निकलते व पटवारी व राजस्व निरीक्षक को यह भूमाफिया खरीद लेते हैं वह खुद का बड़ा-बड़ा रिसोर्ट बनाकर उसमें धंधा आरक्षित होती है उस पर भी कब्जा कर-के लोगों ने खुलेआम बड़ी-बड़ी होटले बनानी चालू कर दि है क्योंकि हर पंचायत क्षेत्र में गोचर भूमि है उन सभी गोचर भूमि में भूमाफियाओं का कब्जा है क्योंकि



भूमाफिया पहले से कर ताक मे रहते हैं सबसे ज्यादा महंगी जमीन है यह गोचर भूमि ही होती है उसको फजीर्वाड़ा मे कर फिर हेरा फेरी करके उस जमीनों को बेच देते हैं फिर कोई बहारी लोग जाकर उसमें फंस जाते हैं फिर उन्हें मजबूरी में इन अधिकारियों की गुलामी करनी पड़ती है पर आदि होगी जब कामबेश्वर महादेव मंदिर के पास पहाडियो वह कोलर की पहाडियों पर भी होटल बननी चालू हो गई रिसोर्ट बनने चालू हो गया क्योंकि पटवारी व राजस्व निरीक्षकों का ध्यान पूरा उस पर रहता है पर धन के आगे सब नतमस्तक रहते हैं धन के आगे किसी की नहीं चलती क्योंकि बड़े अधिकारियों पर दबाव बनाकर धन की मांग करते हैं फिर वह धन लाकर इनको दे देते हैं फिर यह छुटा अधिकारी धन लाकर नहीं देते तो इनका ट्रांसफर करवाया जाता है इन भूमाफियाओ से यह धन की मांग करते हैं फिर भूमाफिया उसका फायदा उठाकर 1 फीट जमीन से हजारों फीट जमीन पर

कब्जा कर लेते हैं वह जवाई बांध क्षेत्र व सैकड़ों बिधा का उल्टे सीधे कब्जे हो रहा है यहां पर राजस्थान सरकार मंत्री महोदय व प्रभारी मंत्री के के बिस्नोई को शिवगंज में मीटिंग करने नहीं दिया जाता है वह जब बारिश नहीं हो रही थी तब सरकार ने प्रभारी सचिव महोदय व बनकर राजस्थान सरकार की ओर से इनको यहां भेजा तब स्थानीय पत्रकारों को कुछ जनप्रतिनिधियों ने यहां की बातें उठाई वह पूरी हकीकत जानकारी उनको बताई तब नाराज हो गई उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाकर इधर व उधर करवा दिया उन्होंने इन अधिकारियों ने इस बार जब वह प्रवास पर आई तब उन्हें स्थानीय पत्रकारों व जनप्रतिनिधियों को बुलाने उचित नहीं



कोलर डुवन गोडाना धुरबाणा क्षेत्र व कामबेश्वर महादेव की पहाडियों में बड़गांव रघुनाथपुरा सहित आसपास क्षेत्रों में कितने बीधा गोचर भूमि पड़ी है उस गोचर भूमि को खुली करवाई जाए वह इन गोचर भूमि पर कितना भूमि पर इनका कब्जा है उसे तुरंत हटाना चाहिए वह जंगली जानवरों के रहने के लिए वहां पर झाड़ियां लगानी चाहिए क्योंकि ऐसे ही महात्मा गांधी नरेगा कर्मचारी फोकट का पैसा उठाते हैं उन्हें हर क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाने का आदेश देना चाहिए कि वहां पर पेड़ पौधे लगाकर जंगली जानवरों के रहने की सुविधा कर सके ऐसे ही इन क्षेत्रों में सैकड़ों तेंदूरे भालू सियांर और लोमड़ी हिरण नीलगाय खरगोश और अन्य जंगली जानवर रहते हैं उनकी रक्षा करने की बात यह लोग करना शिकार करने में सहायता करते हैं यह रिसोर्ट मालिक वह होटल वाले बड़े-बड़े बोर्ड लगाकर अपनी एडवर्टाइज करते हैं वह लोगो को बुलाकर जिप्सी में खुलेआम

घूमते हैं इसके बाद भी इन सरकारी कर्मचारियों की नींद नहीं खुलती और वह लोग जंगली जानवरों का शिकार कर अपना भोजन करते हैं वह इन पहाडियों के पास में जितने भी रिसोर्ट बने उन पर शिकार भुगवाना चाहिए वह सभी जमीन है जो गोचर फौरेसट विभाग जंगल की जमीन है वहां पर जंगली जानवरों के लिए आरक्षित रखनी चाहिए कि लोग आकर यहां पर उनका शिकार न कर सके इस क्षेत्र में जितने भी गाड़ियां खुलेआम घूम रही है उन्हें परिवहन विभाग द्वारा जब्त करनी चाहिए तब जाकर भुगवाना शिव की नगरी कामबेश्वरजी महादेव इलाका है का वह कोलर माताजी की पहाडियों में जंगली जानवर खुल्ले आम रह सकते हैं क्योंकि यहां पर अधिकारी खाली आकर बातें करते हैं नहीं किसी को रोक्ते हैं और नहीं किसी के विरुद्ध कार्रवाई करते तो भविष्य में यह लोग कभी दिखाई नहीं वही लोग यहां पर आकर इन जंगली जानवरों की



रक्षा कर सकते हैं यहां पर कोलर हिल्स नाम से एक बड़ा गोचर भूमि में रिसोर्ट बनाएँ इसके मालिक ने उपखंड अधिकारी में फर्जी डॉक्यूमेंट भेज कर वह तहसील कार्यालय में फर्जी दस्तावेज पेश कर उसका फजीर्वाड़ा करना चाहते हैं लोगों को गुमराह करके जो फजीर्वाड़ा कर देंगे फिर उसे रिसोर्ट में अब बिना स्वीकृत के इतने जोर-जोर से डीजे बजाए जा रहे हैं जिससे जंगली जानवर परेशान हो रहा है अगर इसकी स्वीकृत मिल गई तो समझ लो यह लोग क्या करेंगे सरकारी जमीन को भी नहीं छोड़ेंगे इसलिए जितनी भी सरकारी जमीन फॉरेस्ट लैंड गोचर भूमि पर हुए अतिक्रमण को तुरंत हटाना चाहिए वह यहां पर बैठे पुराने पटवारी राजस्व निरीक्षक व फॉरेस्ट के अधिकारियों को हटाना चाहिए नए अधिकारियों को लाकर वास्तविक स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए नहीं तो यहां की जनता को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा जिसकी तमाम

जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी यह अतिक्रमण करने वाले उल्टा चौर कोतवाल को डॉट पत्रकारो को घमकीया देते है फिर भी यह राजस्व विभाग व फौरेसट विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अभी तक कोई कारवाई नहीं की ईनका क्या कहना है शिवगंज रिसोर्टी तहसील कार्यालय व उपखंड क्षेत्र के पंचायत समिति के क्षेत्रों में सैकड़ों बिधा भूमि पर कब्जा कर लिया है जो जंगलों जानवरों के निवास करने की जमीन पर कब्जा कर बड़ी बड़ी होटलों व रिसोर्ट बनाकर खुल्ले आम धंधा कर रहे हैं वहां पर कोई भी कारवाई नहीं कर रहे है मौली महाराज की धुणी की पहाडियों मे कामबेश्वरजी महादेव मंदिर व कोलर की पहाडियों व आसपास गांवो से हजारो बिधा गोचर व फौरेसट की जमीन पडी है वहाँ पर होटले रिसोर्ट बन गये है प्रशासन कोई कारवाई नहीं कर रहे है कब कारवाई होगी

सम्भागीय आयुक्त महोदया व जिला कलेक्टर को पत्र देने के बाद नियमों के विरुद्ध हुए प्लानो के खिलाफ कार्रवाई क्यू नहीं कर रहे है उपखंड कार्यालय के विरुद्ध

एक को नोटिस नहीं दिया 190 पत्रावलीओ को दस साल हो गया नियम अनुसार पाँच साल में कृषि आधारित उद्योग होने चाहिए

एगो बेस इंडस्ट्रीज नाम पर हुआ घोटाला एससी एसटी की जमीन जनरल के नाम करने करोड़ों में बेचने का धोरखधंधा गरीबों की जमीन अमीरों के नाम पर करने की कार्रवाई पर लगाम लगाएगी सरकार

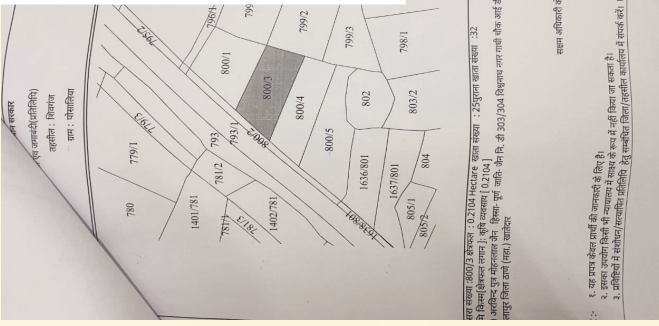
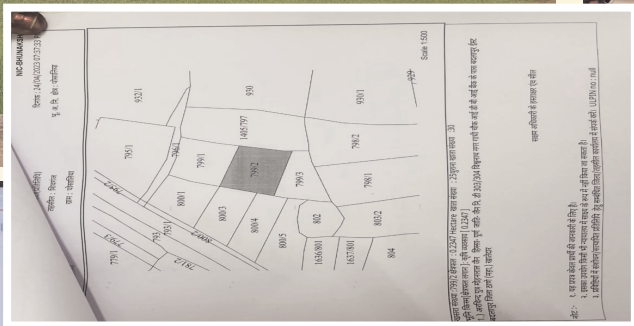
सब एगो बेस इंडस्ट्रीज की जगह पर कट गई कोलोनी पट्टे जारी हो गए अब क्या कार्रवाई होगी

कोलोनीया खारिज कर यह भूमि को वापस एससी-एसटी के नाम होनी चाहिए

भूमाफियाओ ने जनरल वालो को बेच दी कोलोनी स्वीकृत हो गई उपखंड कार्यालय मे स्वीकृत हुई है कोलोनी

नमस्ते राजस्थान

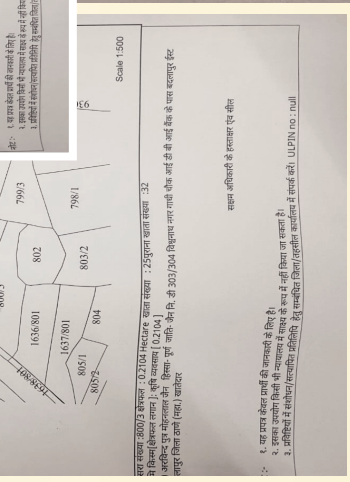
शिवगंज सिरोही जिला कलेक्टर व सम्भागीय आयुक्त महोदया के दौरे को लेकर शिवगंज पाषंद व पूर्व पाषंद जैसाराण माली ने अधिकारीओ के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए जो उपखंड क्षेत्र में कुछ वर्ष पहले एक अभियान चलाया गया था उपखंड अधिकारी द्वारा एगो बेस इंडस्ट्रीज के नाम पर एक गोरख धंधा एससी एसटी की जमीन जनरल के नाम करने का बड़ा ही अनोखा धोरख धंधा इन लोगों ने चालू किया था जिसमें छोटी जमीनों का एगो बेस इंडस्ट्रीज के नाम कर वह जमीन जनरल के नाम रजिस्ट्रेशन होना फिर आम लोगों के साथ धोखाधड़ी करना फिर एससी एसटी लोगों के साथ भी धोखाधड़ी क्योंकि एससी एसटी की जमीन सीधे जनरल के नाम नहीं हो सकती इसलिए उन्होंने एक यह रास्ता निकाला गया था कुछ भूमाफियाओं ने मिलकर शिवगंज शहर वह उसके आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा ही अनोखा धंधा इन लोगों ने किया जो आम गरीबों के साथ धोखाधड़ी अमीरों के साथ सरकार को भी चूना लगाया फिर जनरल के नाम होते ही इन्होंने उसमें बड़ी-बड़ी कालोनियां कटकर लोगों को प्लॉट बेचे गए जो कितना बड़ा धोखा है क्योंकि उसमें नियम था कि अगर जो एगो बेस इंडस्ट्रीज है उसमें 5 साल तक कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगाया जाता तो सत्य व भूमि वापस जिसके नाम की थी उसके नाम हो जाएगी पर इन्होंने एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की 10 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी इन्होंने आज तक नहीं तो नोटिस दिया और नहीं कोई कार्रवाई की उनमें कोलोनी कट गई लोगों के मकान भी बनने चालू हो गए क्योंकि उपखंड अधिकारी वह पटवारी राजस्व निरीक्षक तहसीलदार महोदय रजिस्ट्री करने वाले बाबूजी सब इस गोरख धंधे के अंदर मिले हुए है इनको सरासर पता होने के बाद भी इन्होंने उसमें कॉलोनी कटवा दी प्लान स्वीकृत करवा दी उसमें वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर के अधिकारी भी मिले हुए जिन्होंने लाखों रुपए लेकर काम किया यह काम बहुत सारे हुए क्योंकि क्षेत्र में करीब 190 पत्रावली स्वीकृत हुई है ही इतने हुए तो फिर अन्य जिलों में कितने



हुए होंगे अन्य पंचायत को हो तहसील को कितने हुए होंगे क्योंकि यह गोरख धंधा अब बंद होगा और वापस होगी वह जमीन उसमें जिसके नाम की थी उसके नाम वापस होगी और जिसने भी प्लॉट काँटा है उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज होंगे वह सेठ जमीन वापस उनके नाम हो जाएगी कोलोनी में ओपन क्षेत्र में यह गोरखधंधा सबसे ज्यादा किया करीब 190 पत्रावली एसी थी उसमें यह गोरख धंधा किया गया जो ज्यादातर बड़गांव केसरपुरा चांदाना और अरठवाड़ा पोसालिया सहित आस हाईवे पर करोड़ों रुपए की जमीन इसमें शामिल हुई है जो एक बिधा का भाव करीब 1 करोड़ से अधिक का है उसमें भी यह बड़ा घोटाला किया कोई कमी नहीं रखी इन्होंने भ्रष्टाचार करने में वह अब यह भ्रष्टाचार उजागर होना अब कार्रवाई होगी क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार में यह गोरख धंधा हुआ था पर वापस कांग्रेस सरकार आते ही इस कार्यक्रम को दबा के रख दिया गया अब वापस भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनी है अब यह मामले उजागर होंगे क्योंकि जनता के साथ बड़ा इन लोगों ने धोखा किया है इसमें कुछ नेता लोग भी मिले हुए क्योंकि नेताओं के बिना कोई ऐसा काम हो ही नहीं सकता

शिवगंज उपखंड क्षेत्र के जमीनों के भाव आसमानों में है कहीं पर एक बीघा का भाव दो करोड़ रुपया कहीं पर डेढ़ करोड़ रुपया कहीं पर एक करोड़ रुपए है इस भाव की जमीन में यह घोटाला हुआ है तो समझ जाओ कितने घोटाले हुए होंगे क्योंकि जिस व्यक्ति का हुआ था उस वक्त यह रजिस्ट्रेशन का प्रति बिधा की रेट ₹13000 सरकार अपने कोष में जमा करवा रही थी पर उन भूमाफियाओ को एक बिधा का कम से कम 13 लाख से अधिक का फायदा हो रहा था तो अधिकारियों ने कितना लिया होगा आप हाईवे पर करोड़ों रुपए की जमीन इसमें शामिल हुई है जो एक बिधा का भाव करीब 1 करोड़ से अधिक का है उसमें भी यह बड़ा घोटाला किया कोई कमी नहीं रखी इन्होंने भ्रष्टाचार करने में वह अब यह भ्रष्टाचार उजागर होना अब कार्रवाई होगी क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार में यह गोरख धंधा हुआ था पर वापस कांग्रेस सरकार आते ही इस कार्यक्रम को दबा के रख दिया गया अब वापस भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनी है अब यह मामले उजागर होंगे क्योंकि जनता के साथ बड़ा इन लोगों ने धोखा किया है इसमें कुछ नेता लोग भी मिले हुए क्योंकि नेताओं के बिना कोई ऐसा काम हो ही नहीं सकता

पर कार्रवाई कर यह भूमि सभी बिलानाम कर देने में कोई कमी नहीं रखी और वह हो सकती है बिलानाम दर्ज करवानी चाहिए या फिर उसी गरीब के नाम होनी चाहिए जिसके नाम पहले होती थी क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसा लेना सीखा है गरीबों का भला नहीं करना सीखा इन्होंने हजारों बिधा जमीन ली हुई करोड़ों में बेची गई तो समझो धरती माँ को बेचने में कृषि कितना बड़ा भ्रष्टाचार करते होंगे यह काम कि ए थो जिले में मेरे हिसाब से एक जगह पर ही हुआ होगा सिरोही में नहीं हुआ होगा शिवगंज के अलावा कहीं नहीं हुआ होगा ऐसे ही इस तहसील में रजिस्ट्रेशन के नाम पर इतने बड़े-बड़े घोटाले किए नियमों के विपरीत भी रजिस्ट्रेशन किए लोगों से पैसा वसूल कर लेते थे इनको नियम कानून पता ही नहीं चलता था और इन लोगों ने करोड़ों रुपए लूटे पर इनको शांति अभी तक नहीं हुई अभी तक यही कार्रवाई कर रहे हैं गरीबों को गला घोटकर खुद अरबपति बनने की कोशिश कर रहे हैं गरीबों को धोखा ही दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो सेंट की भूमि थी वह सीधी कन्वेज हो नहीं सकती थी फिर यहां पर उपखंड अधिकारीजी एक श्रीमान व एक बड़े भूमाफियाओ ने मिलकर कुछ भूमाफियाओ की शहर पर प्रति बिधा के हिसाब से ₹13000 बिधा वसूल किया जो कुछ हजारों रुपए खर्च आता था पर इन्होंने अगली जमीन ने करोड़ों रुपए में बेच दी जिसमें अधिकारी भूमाफियाओ व कर्मचारी मिले हुए थे इन्होंने भ्रष्टाचार



खसरा नम्बरा	अपेक्षित	भूमि वर्तमान	कृषक द्वारा भंडन न्यूनतम	विक्रय के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम	अंतराधिकार	दस्तावेज
1636/801	0.1862	कृषि न्यूनतम	0.1862			
1637/801	0.2428	कृषि न्यूनतम	0.2428			
799/1	0.2347	कृषि न्यूनतम	0.2347			
799/2	0.2347	कृषि न्यूनतम	0.2347			
799/3	0.1538	कृषि न्यूनतम	0.1538			
800/3	0.2104	कृषि न्यूनतम	0.2104			
800/4	0.2104	कृषि न्यूनतम	0.2104			
800/5	0.2023	कृषि न्यूनतम	0.2023			
कुल खसरा - B	1.6763		1.6763			

जो कृषि आधारित उद्योग जिसमें नियम दर्ज होनी चाहिए वह जितनी कॉलोनी था की 5 साल तक अगर उसमें वापस वहां पर कोई धंधा (फैक्ट्री) नहीं किया जाता तो सतह ही वह भूमि वापस उस जमीन मालिक के नाम की हो जाएगी जो मुकदमे के लिए एगो बेस इंडस्ट्रीज काटकर प्लाट काट कर बेचे क्योंकि एगो बेस इंडस्ट्रीज में सिर्फ गाय माता के लिए कृषि आधारित उद्योग ही कर सकते थे उसमें इतनी कमाई नहीं होती थी तभी इन्होंने सिर्फ सेंट की जमीन ऐसी की जमीन जनरल ओबीसी के नाम करने के लिए गोरख धंधा किया इस गोरखधंधा में इन्होंने करोड़ों रुपए की चांदी कर ली पर अब कुछ टाइम पहले पता चला कि उन जमीनों में कोलोनी कट गई है तब जाकर पता चला बड़ा ही अनोखा धोखा किया है गरीबों के साथ वह जनता के साथ अब उन अधिकारियों वह और भूमाफियाओ को खिलवाफ कानून निकालना चाहिए तब जाकर इनको पता चलेगा कि भविष्य में कभी किसी जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सके बहुत ही लूट लिया इन लोगों ने वह यह सभी जमीन है वापस एसटी एससी के नाम होनी चाहिए यहां बिलानाम व गोचर में घोषित कर देनी चाहिए

कमल सिंह चौहान उद्योगी एक समाजसेवी शिवगंज सिरोही जिले व शिवगंज तहसील क्षेत्र में सम्भागीय आयुक्त महोदया जिला कलेक्टर के आगमन व लगातार अखबारों द पुलिस पोस्ट में खबर छपने के बाद नहीं जागा प्रशासन फिर अंधा बनकर क्यू बैठा है प्रशासन कार्रवाई क्यू नहीं करते है सरकारी अधिकारी छुप क्यू है यह एगो बेस नामक खुले आम धंधा चालू किया हुआ है जो एक नियमों की बली चढाकर गरीबों के साथ अमीरों व एससी-एसटी की जमीन पर कब्जा करवाकर भूमाफियाओ ने पावर अंटनी लेकर सेठ लोगो ने फायदा उठाया है जो गरीबों के साथ धोखाधड़ी की है अब सम्भागीय आयुक्त महोदया व जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी कार्रवाई करेगे या भ्रष्टाचार ब्यूरो में मुकदमा दर्ज कराना चाहिए सीमादेवी पाषंद नगर पालिका शिवगंज

47 लाख की ठगी का आरोपी जयपुर से गिरफ्तार:स्टॉक मार्केट में कमाई का झांसा देकर एप डाउनलोड करवाया

नमस्ते राजस्थान

कोटा कोटा की साइबर थाना पुलिस ने हाईटेक साइबर ठगी के आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी राजकुमार यादव (24) देवास्थो की ढाणी, जैन छात्रावास के पीछे सांगानेर जयपुर का रहने वाला है। डीएसपी विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी पिछले 8 महीने से फरार चल रहा था। काफी समय से ठिकाने बदलकर छिप रहा था। पहले 3 बार पुलिस को गच्चा देकर भागने में सफल रहा। इस बार भी पुलिस को देखकर आरोपी मकान

की छतों पर भाग गया। जिसे टीम ने पीछा करके पकड़ा। आरोपी को कोर्ट में पेश करके 2 दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपी से ठगी की राशि व घटना में शामिल अन्य साइबर ठगों के बारे में पूछताछ की जा रही है।
ठगी के लिए खाते खुलवाकर हायर किए
शुरूआती पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ठगी करने के लिए लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाते थे। फिर खातेदार को पैसा देकर उन अकाउंट को हायर कर लेते थे। हायर किए

अकाउंट में ठगी का पैसा ऑन लाइन ट्रांसफर करवाते थे। आरोपी राजकुमार ने अपने साथी तेजराज यादव व नफीस मोहम्मद से मिलकर लाखों रुपए की ठगी की है। तेजराज व नफीस को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी।
ये था मामला
14 मार्च को महावीर नगर द्वितीय निवासी रामप्रकाश गोयल ने शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि 20 दिसंबर 2023 को उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप लिंक आया। ग्रुप एडमिन राजीव मेहता ने स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का

झांसा देकर एक एप डाउनलोड करवाया। फिर प्रॉफिट का लालच देकर मेरे से 47 लाख 15 हजार 507 रुपए ऑन लाइन ट्रांजेक्शन करवाए। शिकायत पर पुलिस ने टीम का गठन किया। ठगी के प्रयोग में लिए गए अकाउंट, मोबाइल नम्बरों की जानकारी जुटाई। तकनीकी जांच से आरोपियों तक पहुंची।



अमेजन और फ्लिपकार्ट के 19 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

फेमा नियमों के उल्लंघन का मामला

मुंबई।

अधिकारियों को बुलाया जा सकता है।

ई-कॉमर्स कंपनियां अमेजन और फ्लिपकार्ट विदेशी निवेश से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के कारण प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में आ गई हैं। इस मामले में फेमा नियमों के उल्लंघन के संदर्भ में ईडी ने इन कंपनियों से जुड़े 19 से अधिक ठिकानों पर तलाशी ली है।

रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, बंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और पंचकुला (हरियाणा) में अमेजन और फ्लिपकार्ट के विक्रेताओं से जुड़े 19 से अधिक ठिकानों पर ईडी द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के बाद ये बात सामने आई है। मामला संज्ञान में आने के बाद एजेंसी ने अनियमितताओं के सबूत जुटाने के उद्देश्य से फेमा नियमों के तहत ये तलाशी अभियान चलाया था।



वेंडर्स को फायदा पहुंचाकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। दोनों कंपनियों के खिलाफ शिकायत करने वालों का तर्क है कि इस तरह ये ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अन्य वेंडर्स को समान अवसर नहीं दे रही हैं, जो

कि भारत में फेमा के दिशा-निर्देशों के विपरीत है। सूत्रों की मानें तो ईडी द्वारा तलाशी अभियान चलाए जाने और प्रारंभिक जांच के दौरान मिले सबूतों को इकट्ठा करने के बाद दोनों कंपनियों के टॉप अधिकारियों को तलब करने की संभावना है।

साल 2031 तक 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगी भारतीय अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2031 तक 7 ट्रिलियन डॉलर के आकार तक पहुंचने की उम्मीद है। इस ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान देश की जीडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि, वित्त वर्ष 2025

से लेकर 2031 तक की वार्षिक वृद्धि दर महामारी से पहले के दशक की औसत वृद्धि दर (6.6 प्रतिशत) के आसपास होगी। इस विकास को मुख्य रूप से पूंजीगत खर्च और उत्पादकता में सुधार से प्रेरित बताया गया है। 2023-24 के चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी विकास दर 6.8 प्रतिशत तक रहने की संभावना है, जिसका कारण उच्च ब्याज दरें और सख्त लॉडिंग नियम हैं, जिससे शहरी मांग पर असर पड़ा है। इस रिपोर्ट में यह

भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने के प्रयासों का प्रभाव अर्थव्यवस्था के विकास पर देखने को मिलेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 2024-25 में औसत 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 5.4 प्रतिशत से कम होगी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि मौसम की स्थिति और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ विकास और महंगाई के लिए महत्वपूर्ण जोखिम हैं। इस

वर्ष खरीफ की बुआई अधिक हुई है, लेकिन बेमौसम बारिश और अन्य मौसम संबंधित प्रभावों को लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि भू-राजनीतिक तनाव के कारण आपूर्ति श्रृंखलाएँ प्रभावित हो सकती हैं, व्यापार में विघ्न आ सकता है और तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जो महंगाई और इनपुट लागत को प्रभावित कर सकती है।

बीते एक साल से निवेशकों को निराशा कर रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर

नई दिल्ली।

पिछले कुछ दिनों से शेयर मार्केट में गिरावट जारी है। हालांकि मंगलवार को शेयर मार्केट में काफी दिनों बाद तेजी दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर देश की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ समय से निवेशकों को निराशा कर रही है। मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयर की कीमत पिछले एक साल काफी गिर गई है। मंगलवार को रिलायंस के शेयरों में एक फीसदी से ज्यादा की तेजी आई। यह तेजी काफी समय बाद दिखाई दी है। इसके बावजूद इसकी कीमत पिछले 11 माह के स्तर पर है। पिछले एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के

शेयर में 8 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। एक साल पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत 1174.68 रुपये थी। अब इस शेयर की कीमत 1277.15 रुपये है। इसके बाद शेयर में एक साल में करीब 8.60 फीसदी की ही तेजी आई है। मंगलवार को इसकी कीमत में उतार-चढ़ाव जारी था। निफ्टी 50 ने एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज से बेहतर प्रदर्शन किया है। निफ्टी 50 में देश की टॉप 50 कंपनियां होती हैं। निफ्टी 50 एक साल पहले 19694 अंक पर था। अभी यह करीब 23,747 पर है। रिलायंस का शेयर इस साल जुलाई में 1608 रुपये पर पहुंच गया था। यह इसका अब तक का हाई है। लेकिन अपने हाई

पर पहुंचने के बाद मानों मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयर पर किसी की नजर लग गई। इसके बाद इसमें गिरावट का दौर शुरू हो गया। इसके बाद जुलाई से लेकर अब तक इसमें 20 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। वहीं पिछले एक महीने में रिलायंस का शेयर करीब 6.80 फीसदी गिर गया है। वहीं पिछले 6 महीने में भी इसमें तगड़ी गिरावट आई है। इतने समय में यह 11 फीसदी से ज्यादा गिर गया है। गिरावट के बावजूद जानकार इस शेयर को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदकर रखा जा सकता है। कंपनी ने लॉन्ग टर्म में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है।

आज शेयर बाजार रहेगा बंद, इस हफ्ते तीन दिन नहीं होगी ट्रेडिंग

दिसेंबर महिने में 10 दिन नहीं होगा कारोबार, बाजार रहेगा बंद

नई दिल्ली। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है। इस वजह से शेयर बाजार बंद रहेगा। इस दौरान शेयर बाजार में किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग नहीं होगी। शेयर बाजार में कब छुट्टी रहती है, इसे लेकर बीएसई और एनएसई साल का कैलेंडर जारी करते हैं। चूंकि कई बार ऐसे मौके आते हैं जब किसी दिन छुट्टी के बारे में कैलेंडर में जानकारी नहीं होती है। ऐसे में बीएसई और एनएसई नोटिफिकेशन के जरिए छुट्टी की घोषणा करते हैं। शेयर बाजार में इस हफ्ते भी तीन दिन छुट्टी रहेगी। पिछले हफ्ते भी तीन दिन छुट्टी थी। पिछले हफ्ते 15 नवंबर को गुरुनानक जयंती के मौके पर शेयर बाजार बंद था। इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी हो गई थी। बता दें दिसेंबर में 10 दिन कारोबार नहीं होगा। 10 दिन शेयर बाजार बंद रहेगा। इसमें 4 शनिवार और 5 रविवार शामिल हैं। इसके अलावा 25 दिसेंबर को क्रिसमस के मौके पर भी शेयर मार्केट बंद रहेगा। मंगलवार को शेयर मार्केट में काफी दिनों बाद तेजी देखी गई। सेंसेक्स एक हजार अंकों से ज्यादा उछला। वहीं निफ्टी में भी 300 अंकों से ज्यादा की तेजी आई। शेयर बाजार में इस तेजी के साथ निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा मिला।



इंडोनेशिया में आईफोन 16 पर बैंन हटवाने दिया 844 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव

मुंबई।

इंडोनेशिया में एप्पल ने आईफोन 16 पर लगे बैंन को हटवाने के लिए सरकार को 844 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव दिया है। कंपनी के सूत्रों के मुताबिक, एप्पल ने अपना निवेश प्रस्ताव करीब दस गुना बढ़ा दिया है। यह कदम इंडोनेशिया सरकार को आईफोन 16 पर बैंन हटाने के लिए मनाने की नई कोशिश के रूप में सामने आया है। एप्पल अब दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अगले दो साल में करीब 844 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल को पहले का निवेश प्रस्ताव केवल 10 मिलियन डॉलर (करीब 84 लाख रुपए) का था। लेकिन अब एप्पल ने अपनी निवेश राशि में भारी वृद्धि की है। इंडोनेशिया के उद्योग मंत्रालय

ने अभी प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी है, हालांकि पिछले माह आईफोन 16 की बिक्री पर बैंन लगा दिया गया था। इंडोनेशिया सरकार ने बैंन के बाद एप्पल से कहा था कि वहां अपने स्मार्टफोन के लिए रिसर्च और विकास पर ज्यादा ध्यान दे और लोकल मैयुफेक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अपनी निवेश योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। मंत्रालय का कहना है कि एप्पल ने अपने पिछले निवेश के तहत डेवलपर अकादमियों के माध्यम से लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपिया (करीब 801 करोड़ रुपए) का निवेश किया था, जो कि उसकी घोषित प्रतिबद्धता से कम था। एप्पल के अधिकारियों को पहले इंडोनेशिया के उद्योग मंत्री अंगुस गुमीवांग कार्तसमित्ता से मिलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब वे जकार्ता पहुंचे, तब उन्हें बताया गया कि मंत्री उपलब्ध नहीं हैं। इसके



बाद उन्हें मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल से मिलना पड़ा। यह घटना एप्पल के निवेश प्रस्ताव और सरकार के साथ बातचीत में अहम मोड़ साबित हुई। इंडोनेशिया सरकार का कहना है कि एप्पल की लोकल यूनिट ने स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए 40 प्रतिशत स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल करने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया, इसलिए आईफोन 16 की बिक्री को बैंन कर दिया गया।

सीसीआई ने मेटा पर लगाया 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना

वॉट्सएप पर पांच साल तक मेटा के साथ डेटा साझा करने पर रोक

नई दिल्ली।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने मेटा प्लेटफॉर्म पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना ठेका है। यह जुर्माना वॉट्सएप की 2021 की प्राइवसी पॉलिसी के जरिए मेटा द्वारा अपने प्रभावशाली बाजार स्थिति का दुरुपयोग करने के कारण लगाया गया है। यह फैसला पॉलिसी को कैसे लागू किया गया और यूजर्स का डेटा कैसे इकट्ठा और मेटा कंपनियों के साथ साझा किया गया। इसके अलावा सीसीआई ने मेटा और वॉट्सएप को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे एक तय समयसीमा के अंदर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें। सीसीआई ने आदेश दिया है कि वॉट्सएप अगले पांच साल तक मेटा कंपनियों के साथ विज्ञापन के लिए यूजर्स का डेटा साझा नहीं कर सकता है। इस अवधि के बाद यूजर्स को यह विकल्प दिया जाना चाहिए कि वे गैर-सेवा संबंधी डेटा शेयरिंग से बाहर हो सकें। इसके साथ ही वॉट्सएप को यह साफ तौर पर बताया होगा कि मेटा कंपनियों के साथ कौन-सा डेटा साझा किया है,

उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उसका उद्देश्य क्या है। यह फैसला वॉट्सएप के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि भारत में इसके 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। सीसीआई ने वॉट्सएप को 2021 की सेवा शर्तों और प्राइवसी पॉलिसी को लेकर यह फैसला सुनाया है। इस पॉलिसी में यूजर्स को मेटा कंपनियों के साथ डेटा शेयरिंग की नई शर्तें स्वीकार करना ज़रूरी किया था अन्यथा वे ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उस समय ने ऐप के भीतर नोटिफिकेशन भेजकर यूजर्स को 8 फरवरी, 2021 तक इन शर्तों को मानने को कहा था। यह पॉलिसी 25 अगस्त, 2021 की पुरानी पॉलिसी से अलग थी, जिसमें यूजर्स को फेसबुक के साथ डेटा शेयरिंग से ऑफ आउट करने की सुविधा दी गई थी।

सीसीआई ने कहा कि वॉट्सएप की 2021 की पॉलिसी ने लो या छोड़ दो- की तरह थी, जो उपयोगकर्ताओं को मेटा ग्रुप के साथ डेटा शेयरिंग की शर्तें ज़रूरी रूप से स्वीकार करने पर मजबूर करती थी। इसे आयोग ने अनुचित शर्त माना है। पिछले साल सीसीआई ने गूगल के एंड्रॉइड मामले में 133.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और कंपनी से बिजनेस मॉडल में बदलाव करने को कहा था।

रुपया गिरावट पर बंद

नई दिल्ली।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मंगलवार को भारतीय रुपया दो पैसे की गिरावट के साथ ही 84.43 पर बंद हुआ। गत दिवस रुपया 84.41 पर बंद हुआ था। वहीं आज सुबह रुपया 84.07 पर खुला। इससे पहले सोमवार को रुपया पांच पैसे की बढ़त पर बंद हुआ। गत दिवस सुबह विदेशी पूंजी की निकासी के बाद भी रुपया 84.38 प्रति डॉलर पहुंच गया था। यह निम्नतम स्तर से ऊपर उठकर आठ पैसे की बढ़ोतरी दिखाता है। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने बताया कि तेल की कीमतों में गिरावट के कारण ही मुद्रा में सुधार आया। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपया 84.42 प्रति डॉलर पर खुला और शुरुआती सौदों के बाद 84.38 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। इस बढ़ोतरी के बावजूद रुपया गुरुवार को 84.46 पर बंद हुआ था। वहीं अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.06 फीसदी की बढ़त के साथ 106.68 पर रुका। विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई ने गुरुवार को 1,849.87 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जो दिखाता है कि वे बाजार में बिकवाल रहे। विदेशी मुद्रा बाजार में निर्धारित संबंधों के बावजूद, रुपया ने एक मजबूत प्रदर्शन किया और अमेरिकी डॉलर को मुकाबले काफी मजबूती दिखाई।

सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये उछाल दुनिया भर से मिले मिले-जुले संकेतों के बाद भी खरीदारी हावी रहने से हुआ है। सुबह कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स 266 अंकों की बढ़त के साथ 77,605 पर कारोबार करता दिखा, जो 0.34 फीसदी की बढ़त दिखाता है जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 83.70 अंकों तकरीबन 0.36 फीसदी की तेजी के साथ 23,537 का स्तर पर पहुंच गया।



नमस्ते राजस्थान



राजस्थान

08

भीलवाड़ा

बुधवार 20 नवम्बर 2024

खबरों की सत्यता, निष्पक्षता, पारदर्शिता

आखरीया भट्टे के पिछे पडी सरकारी जमीन बनाएँ जाने वाले पट्टे को खारिज करवें

श्री जी नगर से बहार पडी राजमाताजी की जमीन पर कब्जा करवाकर पट्टा बनाकर देने की तैयारी वालों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए

जमीन सरकारी पर कब्जा कर परिवार को बेचा ईस जमीन पर राजमाताजी धर्मशाला की स्वीकृति प्रदान करावे

एक कांग्रेसी नेताओं व बहारी लोगो को पट्टे बनाने वालों के पट्टे खारिज करावे

नमस्ते राजस्थान

शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र के सबसे महंगे क्षेत्र के आखरीया भट्टे पर जितना फिट कब्जा किया उठने का पट्टा बनाकर नगर पालिका ने दे दिया करोड़ों की जमीन पर फोकट में पट्टा जारी किया क्या करें एक समुदाय के होने से इनका फायदा इस वाले पालिका के कांग्रेस बोर्ड ने दिया सरकार द्वारा 91 रेगुलराइज का सरकार नियम अनुसार है कि जिसका वह उसके परिवार के नाम पर कहीं पर मकान या प्लॉट नहीं हो या किसी प्रकार का सरकार से कोई फायदा नहीं लिया हो उनको ही भुखंड का पट्टा दिया जा सकता है पर शिवगंज नगर पालिका ने तो उल्टा ही काम कर दिया जिनके परिवार के नाम पर मकान है प्लॉट है उसको भी करीब 6000 फीट से अधिक का पट्टा जारी कर दिया एक परिवार को ऐसा ही उनका मकान व पलोट बीसलपुर में मकान के पट्टे होने के बाद भी यहां पर करीब 6000 से अधिक फिट का मुख्य रोड पर पट्टा जारी कर दिया गया प्लॉट के आजू-बाजू को तीन रास्ते गुजरते हैं वह पट्टा देखकर नगर पालिका के अधिकारी अध्यक्ष ने मिलकर पालिका को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया यह वसूली ईन अधिकारियों व पालिकाध्यक्ष से होनी चाहिए और उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार ब्यूरो में मुकदमा दर्ज करवा कर इन दोषियों को जेल भेजना उचित रहेगा यह क्या करते हैं इनके बड़े नेता के इशारे पर और अपने वोट बैंक के चक्कर में फर्जी पट्टे जारी कर रहे हैं ऐसे ही शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र के छिपावास नुककड़ पर भी ऐसा ही पट्टा जारी किया है विश्व सूत्रों के अनुसार छिपावास नुककड़ पर एक बड़ा भूकंप जिसका पट्टा अभी चुनाव से 2 दिन पहले वोट बैंक के चक्कर में चुनाव से दो दिन पहले बैंक डेट में जारी कर दिया जिस भुखंड के लिए शिवगंज



नगर पालिका क्षेत्र पूरा वह शहर का पूरा बाजार बन्द रहा था बड़ा आंदोलन हुआ था बहुत ही बड़ी रैली निकाली थी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी दिया था वह नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग को खत्म कर वह भुखंड का पट्टा नहीं देने के लिए पालिका पर दबाव बनाया था पालिका प्रशासन शिवगंज उसको रोक कर उस मीटिंग को खारिज कर दिया था अब चुनाव के दो दिन पहले जानकारी को नहीं देना चाहिए था ईस भुखंड के सामने ही एक मंदिर है मंदिर के पुजारी द्वारा उस भूमि में जब मेला भरा जाता है तब वहां पर भोजन

प्रसादी का आयोजन किया जाता है और उस भुखंड के पास ही एक समुदाय ने नगर पालिका द्वारा स्नान नहीं चाहते यह लोग सब एक हो कर रहे क्योंकि ऐसा कर दिया तो सिर्फ नदी किनारे तक कुछ लोग कब्जा कर निवास कर रहे हैं उन्हें हटाना तो उनको उचित नहीं समझा और प्रशासन शिवगंज के लिए चारदीवारी बनाकर रखी थी उसी का पट्टा जारी कर दिया शहर में कोई विवाद न बढ़ जाए और ऐसा शहर में शांति भंग हो नही हो फिर इन नेताओं को क्या लाना देना नेताजी तो सुरक्षित रह जाते हैं और शिवगंज की जनता को आपस में झगड़ा करा कर खुद आनंद उठा लेते हैं शिवगंज शहर एक



प्रशासन को राजस्व का करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहे हैं इन लोगों ने सब नुकसान किया वो इन नेताओं से पता चले कि भविष्य में ऐसे पट्टे जारी न करें जिसका पालिका प्रशासन को नुकसान हो वह खुद का वोट बैंक बढ़ जाए इन पट्टे के लिए पालिका में पूर्व में आपत्ति लगी हुई है और आपत्ति लगी जाती है उस आपत्ति की सुनवाई भी नहीं करते बिना सुने ही इसका पट्टा दो दिन पहले दिया उस पट्टे का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए उपखंड अधिकारी महोदयजी व तहसीलदार महोदयजी से शिवगंज शहर की जनता का अनुरोध किया जाता है कि यह पट्टा का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सौदा यह पट्टा खारिज होना चाहिए आखरीया भट्टे वाले दोनों पट्टे 12000 स्क्वायर फीट जो 6000 प्लस 6000 फीट से अधिक के बाद करीब करोड़ों रुपए की जमीन आनन फानन में फोकट में दे दी और पालिका को करोड़ों का चूना लगा दिया इन लोगों ने यह पता चलना चाहिए सरकार को चूना लगाने वालों के बीच तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए वह जो नुकसान पालिका प्रशासन को पहुंचा उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए अपने वोट बैंक के चक्कर में पालिका को नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारी विरुद्ध कार्यवाही होगी तब जाकर उनको पता चलेगा कि भविष्य में राजस्व का नुकसान नहीं पहुंचा सके भ्रष्टाचार ब्यूरो के निर्देश अनुसार जो सरकार को 50000 से अधिक का

नुकसान पहुंचाते हैं उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना आवश्यक होता है ऐसे पालिका प्रशासन ने इन दोनों को पट्टा देकर पालिका को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है इसलिए उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार ब्यूरो में तुरंत मुकदमा दर्ज करवाना आवश्यक होता है और इन दोषियों को जेल होनी चाहिए वह पालिका को आगे भविष्य में कोष का नुकसान नहीं पहुंचा सके इसलिए अधिकारियों सहित नेताओं के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज करवाना आवश्यक है और ऐसे पट्टे को तुरंत खारिज कर यह जमीन पालिका को अपने कब्जे में लेनी व तारबंदी करनी चाहिए और वहां पर गरीबों के लिए छोटे प्लॉट काटकर देना चाहिए यहां गरीबों के लिए प्लॉट बनाकर देना चाहिए जिससे गरीब 300 या 400 परिवार निवास कर सकें और उन गरीबों को एक छत जरूर मिल जाएगी जिसने भी नियम विरुद्ध पट्टे जारी किए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए इनका क्या कहना है शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र में आखरीया भट्टे पर दो बड़ी सरकारी जमीन पर एक ही समुदाय के लोगों को बड़े पट्टे बनाकर देना और सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए और भ्रष्टाचार ब्यूरो में मुकदमा दर्ज कराना चाहिए और यह पट्टे खारिज करना चाहिए

वास नुककड़ पर एक समुदाय को पट्टा दिया गया जो नियम विरुद्ध है ईस पट्टे के लिए पालिकाध्यक्ष ने बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी पुरा शहर बन्द रहा था बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था शिवगंज शहर एक हुआ था चुनाव के दो दिन पूर्व वोट बैंक के चक्कर में पट्टा जारी कर दिया जो शिवगंज की जनता के साथ धोखाधड़ी है तुरंत खारिज करना चाहिए यह पट्टा और रामदेवजी मंदिर मेले के लिए भोजन प्रसादी के लिए आरक्षित करनी चाहिए

सीमा देवी माली पाषंद नगर पालिका शिवगंज

शिवगंज के आखरीया भट्टे पर एक ही समुदाय के दो पट्टे बनाए गए वह शांति नगर में 12000 स्क्वायर फीट वह 7000 फीट सरकारी जमीन पर कब्जा करवाकर पट्टा बनाकर देने उसको फिर जमीन की पट्टा बनाने की तैयारी में पालिका प्रशासन बड़ी रकम लेकर पट्टा बनाने का ठेका भी ले लिया है कुछ दलालों के भरोसे चल रही नगर पालिका वह पालिका में दलाल अधिकारियों तक धन पहुंचाते हैं ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए वह सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करवा कर पालिका प्रशासन उसको पट्टे जारी कर रही है वह कितना गलत है इस जमीन पर राजमाताजी की धर्मशाला का निर्माण हो तो शहर का और भला हो जाएगा तभी सब की जांच करवाकर ऐसे भ्रष्टाचारियों को तुरंत जेल भेजना चाहिए

कमल सिंह चौहान उधमी एव समाज सेवी रिको शिवगंज

देवली-उनियारा थप्पड़ कांड पर सीकर में विरोध-प्रदर्शन:मीणा समाज ने सिर पर कफन बांधकर कलेक्ट्रेट को घेरा, बोले- नरेश मीणा को रिहा करें

सीकर राजस्थान के देवली-उनियारा में विधानसभा उप चुनाव में हुए थप्पड़ कांड के बाद निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा के समर्थन में आदिवासी मीणा समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सीकर में आज मीणा समाज के लोगों ने सिर पर कफन बांधकर आक्रोश रैली निकाली और कलेक्ट्रेट का घेराव कर विरोध-प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने आरोपी नरेश मीणा को जल्द रिहा करने की मांग की है। राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ (सीकर) की जिला कार्यकारी अध्यक्ष सीमा मीणा ने कहा- समरावता गांव में के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा इलेक्शन के खिलाफ जो प्रशासन

ने बर्बरता पूर्ण कार्रवाई की गई है, उससे मीणा समाज के लोगों में आक्रोश है। लोग आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है जो गलत है। नरेश मीणा को जल्द रिहा किया जाए और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। महामंत्री बाबूलाल मीणा ने कहा- नरेश मीणा ने गलती की है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं लेकिन पहले जिसने गलती की उसे कोई नहीं देख रहा। एसडीएम का रिकॉर्ड भी पहले से ही बहुत खराब है। एसडीएम अभित चौधरी का आचरण अभद्र, तानाशाही और दबंगई वाला रहा है। सरकार ने उनको हिंडोली उपखंड

अधिकारी के पद से एपीओ किया था। उनके द्वारा मालपुरा नगर पालिका क्षेत्र में नियम कायदों को ताक में रखकर तोड़फोड़ करने के मामले में कार्मिक विभाग ने जांच के आदेश जारी किए हैं।

जबरन मतदान कराना अपराध

बाबूलाल मीणा ने कहा- एसडीएम अब फंस चुका है। उसने एक अपाहिज महिला से जबरन मतदान कराया था, सबसे पहले अपराध वह है। जब जबरन मतदान कराया जा रहा था तो नरेश मीणा उसके विरोध में आया था। नरेश ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने कहा- अगर नरेश मीणा पर मुकदमा दर्ज हुआ है तो एसडीएम पर

क्यों नहीं हुआ। घटना के दौरान कलेक्टर साहिबा मौके पर क्यों नहीं गई, उन्हें जाना चाहिए था। उप चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। नरेश मीणा ने उस हत्या को रोकने की कोशिश की थी। बाबूलाल मीणा ने कहा- नरेश मीणा सिर्फ मीणा समाज का कार्यकर्ता ही नहीं है। वह 36 कौम का कार्यकर्ता है। वह हर आदमी के लिए लाठी खाता है, पुलिस की लाठियों से उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। आधी रात को पुलिस वालों ने गांव में घुसकर मारपीट की। इस घटना में मीडियार्कर्मियों पर जो हमला हुआ है, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं लेकिन रमेश मीणा को न्याय मिलना चाहिए। मीणा

समाज के लोगों ने कहा- प्रदेश लेवल पर बड़ी मीटिंग होने जा रही है। आज आदिवासी मीणा समाज के लोगों द्वारा सभी जिलों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसके बाद संभाग स्तर पर मीटिंग होगी। हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री कब तक इस मामले में संज्ञान लेते हैं।

अगर संज्ञान नहीं लिया तो हम मानवाधिकार आयोग में जाएंगे। इसके बाद सड़कों पर बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए समाज के लोग 7 दिनों बाद प्रत्येक गांव-ढाणी में जाकर पीले चावल बांटे जाएंगे। जिसके बाद फिर से सड़कों पर बड़ा आंदोलन होगा।